राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

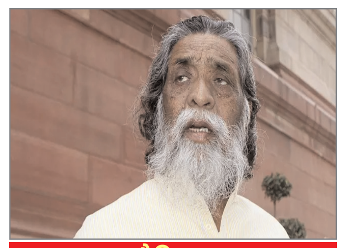

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, मंगलवार, 24फरवरी 2026
वर्ष 14, अंक 305, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

विद्युत संविदा कर्मियों का हल्ला बोलः 25,000 वेतन और नियमितीकरण की मांग...03

जिले में 85 स्वीकृत पदों की जगह 36 चिकित्सक दे रहे सेवाएं...04

रेप की स्नद्धक्रपर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद- भाजपा पर भरोसा नहीं, किसी और राज्य की पुलिस करे जांच

●पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज हुई है. अविमुक्तेश्वरानंद आरोपों को 'मनगढ़ंत' बता रहे हैं और सनातन को बदनाम करने की साजिश कह रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह पुलिस का जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन उन्हें भाजपा पर भरोसा नहीं है।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. पॉक्सो कोर्ट के निर्देश पर अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ रविवार को स्नद्धक्र दर्ज की गई और आज उन्हें पुलिस हिरासत में ले सकती है. उनके ऊपर यौन शोषण के गंभीर आरोपों में स्नद्धक्र दर्ज की गई है. स्नद्धक्र पर प्रतिक्रिया देते हुए अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, 'हमारा अंतकरण हमारे साथ है, हम निर्दोष है, ये सब बनावटी है. जो कहानी गढ़ी गई वो झूठी सिद्ध होगी. हम आपके कैमरों की जद में थे, पुलिस ने हमारे साथ ज्यादती की। '

उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामलों की जांच पर कहा कि भाजपा शासित पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं, उनकी मांग है कि गैर भाजपा शासित पुलिस इस मामले की जांच करे. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जांच के लिए कोई भी पुलिस आए हम पूरा सहयोग करेंगे. शंकराचार्य ने मीडिया से कहा, 'अभी गिरफ्तारी की स्थिति तो नही है, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी होती है तो ये कालनेमी की शंकराचार्य को अपमानित करने वाला प्रयास होगा। '

बता दें, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पिछले साल अपने कैंप में दो नाबालिग लड़कों के कथित शोषण का आरोप है. इन लड़कों पर प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ में भी शोषण का आरोप है. जबकि अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि वे लड़के कभी उनके गुरुकुल में नहीं आए, कभी पढ़े नहीं और हमारा उनसे कोई लेना-देना नहीं है. अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सीडी-सीडी कह कर भ्रम फैलाया जा रहा है. सीडी किस चीज की है. उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है. ऐसे कई सवाल हैं, जिनका जवाब आने वाले दिनों में पूछा जाएगा।

अगर गिरफ्तार करेगी पुलिस, तो हम विरोध नहीं करेंगे

अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, 'अगर पुलिस हमें अरेस्ट करने के लिए एक्शन भी लेती है, तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे. हम कोऑपरेट करेंगे. पब्लिक सब देख रही है... कहानी झूठी साबित होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों. हम आपके कैमरों की पहुंच में थे. प्रयागराज में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं।

अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि गऊ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की हमारी मांग को दबाने के लिए सरकार का ये कुत्सित प्रयास है. सनातन को नष्ट करने के लिए कुछ लोग चोला पहन कर आ गए हैं. ये लोग हिंदू चोला पहनकर हिंदू धर्म, सनातन को नष्ट कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि शंकराचार्य वश में नहीं आने वाले हैं।

बनारस पहुंची पुलिस, अविमुक्तेश्वरानंद से हो सकती है पूछताछ

एफआईआर दर्ज होने के एक दिन बाद प्रयागराज के झूंसी थाने से पुलिस की टीम बनारस पहुंच गई है. यह टीम अविमुक्तेश्वरानंद पूछताछ कर सकती है. पॉक्सो जज विनोद कुमार चौरसिया ने शनिवार को झूंसी पुलिस स्टेशन को अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने का आदेश दिया था। यह आदेश कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह टाइटल विवाद में वादी शंकुरी पीठाधीश्वर आशुतोष महाराज की याचिका पर आया. अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के अलावा, शिकायत में तीन अज्ञात लोगों का नाम था. स्टेशन ऑफिसर (झूंसी) महेश मिश्रा ने टीओआई को बताया कि एफआईआर बीएनएस(क्रिमिनल इंटिमिडेशन) की धारा 351(3) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5, 6, 3, 4(2), 16 और 17 के तहत दर्ज की गई थी।

जेल में बंद कैदियों के लिए बाहर से नहीं आएगा इफ्तार का सामान, राजस्थान जेल प्रशासन का आदेश

●राजस्थान जेल विभाग ने रमजान में मुस्लिम कैदियों को सीधे इफ्तार-सहरी का खाने देने पर रोक लगा दी है. अब सभी सामान अधिकृत जेल कंज्यूमर स्टोर से ही खरीदनी होगी. जमीत-उल-कुरैश के वाइस-प्रेसिडेंट इलियास कुरैशी ने कहा, 'ऐसे इंतज़ाम डिपार्टमेंटल स्टोर के ज़रिए मुमकिन नहीं हो सकते, क्योंकि कम्युनिटी द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए इफ्तार पैकेट में आमतौर पर दी जाने वाली वैरायटी और न्यूट्रिशनल वैल्यू को कॉपी करना मुश्किल हो सकता है'

रमजान के पवित्र महीने में राजस्थान के जेल डिपार्टमेंट ने एक हैरान करने वाला कदम उठाया है. डिपार्टमेंट ने जेल में बंद कैदियों को लोगों और ऑर्गनाइजेशन को मुस्लिम कैदियों को सीधे इफ्तार और सहरी का खाना देने से रोक दिया है और आदेश दिया है कि रमजान का सारा सामान सिर्फ ऑथराइज़्ड जेल कंज्यूमर स्टोर से ही खरीदा और बांटा जाए।

रमजान के दौरान जब कई मुस्लिम ऑर्गनाइजेशन को जेल प्रशासन ने जेल से वापस भेज दिया गया और उनका समान भी ले जाने के लिए कहा. बता दें कि सामाजिक और धार्मिक ग्रुप पारंपरिक रूप से रोजा रखने वाले कैदियों को फल, खजूर और पैकेज्ड खाना देते रहे हैं. जेल हेडक्वार्टर की ओर से 17 स्नद्गड्ढ को जारी आदेश के तहत, डोनर को जेल के अंदर कंज्यूमर स्टोर पर ऑर्डर देना होगा. स्टोर सामान खरीदेगा, डोनर से सीधे पेमेंट लेगा और जेल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए कैदियों को सामान भेजेगा।

बाहर का कोई खाना या सामान नहीं जाएगा जेल

आदेश में कहा गया है कि जेल परिसर के अंदर बाहर से कोई भी खाने का सामान गिफ्ट के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. यह निर्देश पूरे राजस्थान में सभी सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट और सब-जेलों पर लागू होता है, जिसमें महिला सुधार गृह, स्पेशल सेंट्रल जेल, हाई-सिक्योरिटी जेल, ओपन जेल और जुवेनाइल होम शामिल हैं. राजस्थान में आठ सेंट्रल जेल, 28 डिस्ट्रिक्ट जेल और कई सब-डिस्ट्रिक्ट जेल हैं. टीओआई से बात करते हुए, डायरेक्टर जनरल (जेल), अशोक राठौर ने कहा कि यह कदम मौजूदा नियमों के हिसाब से है।

राठौर ने कहा, 'ऑर्डर में कुछ भी गलत नहीं है. बाहर के खाने पर कुछ पाबंदियां हमेशा से थीं. सिक्योरिटी और सेफ्टी के नजरिए से बाहर से मिलने वाले खाने पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता.' उन्होंने आगे कहा कि डोनर अभी भी जेल के तय स्टोर से सामान खरीदकर खाना होस्ट कर सकते हैं और डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पक्का करेगा।

रोजे में जरूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू जेल स्टोर में नहीं

जमीत-उल-कुरैश के वाइस-प्रेसिडेंट इलियास कुरैशी ने कहा कि ग्रुप आमतौर पर खजूर, फल, स्नैक्स और ड्रिंक्स के साथ इफ्तार पैकेट तैयार करते हैं. उन्होंने कहा, 'ऐसे इंतज़ाम डिपार्टमेंटल स्टोर के ज़रिए मुमकिन नहीं हो सकते, क्योंकि कम्युनिटी द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए इफ्तार पैकेट में आमतौर पर दी जाने वाली वैरायटी और न्यूट्रिशनल वैल्यू को कॉपी करना मुश्किल हो सकता है।'

कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव ने नए सिस्टम के प्रैक्टिकल असर पर भी चिंता जताई. प्रोग्रेसिव मुस्लिम अलायंस के प्रेसिडेंट, अदुल सलाम जौहर ने कहा कि सेहरी और इफ्तार के खाने के लिए खास और न्यूट्रिशन से भरपूर चीज़ों की जरूरत होती है जो पूरे दिन रोज़ा रखने वालों के लिए सही हों।

रमजान के दौरान रोजा

बता दें, रमजान के पवित्र महीने में मुसलमान 30 दिनों तक रोजे रखते हैं. जिसमें वह सूरज निकलने से पहले से लेकर सूरज डूबने तक बिना खाए पिए रहते हैं. 13 से 15 घंटों तक भूखे प्यासे रहने के लिए, शरीर को खास न्यूट्रिशनल वैल्यू की जरूरत होती है. सामाजिक संगठनों का तर्क है कि यह न्यूट्रिशनल वैल्यू जेलों में नहीं मिल सकती है. साथ ही जेल स्टोर से खरीदने की कंडीशन राइट टू चॉइस के अधिकार का भी उल्लंघन है।

संक्षिप्त ख़बरें

घर के आंगन में रखा था पिता का पार्थिव शरीर, इकलौते बेटे ने पहले बोर्ड परीक्षा दी, फिर मुखाग्नि

मेरठ। एक तरफ बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका तो दूसरी तरफ पिता को अंतिम विदाई। पंजाबीपुरा निवासी कक्षा 10 के छात्र कुशल जैन की शनिवार को 'दोहरी परीक्षा' थी। एक तरफ उसे अपने भविष्य की परीक्षा देनी थी तो दूसरी तरफ कर्तव्य की परीक्षा भी पास करनी थी। कुशल ने असाधारण धैर्य का उदाहरण देते हुए यह दोनों जिम्मेदारियां निभाई। पहले बोर्ड की परीक्षा दी और फिर पिता का अंतिम संस्कार किया। पंजाबीपुरा गली नंबर एक में शनिवार सुबह सन्नाटा था। घर के आंगन में 45 वर्षीय आशु जैन का पार्थिव शरीर रखा था। शुक्रवार शाम लगभग सात बजे उनका बीमारी के चलते निधन हो गया था। वह एक निजी कंपनी में काम करते थे। उनके इकलौते पुत्र कुशल जैन की शनिवार को अंग्रेजी की परीक्षा थी। वह द अध्ययन स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ते हैं। उनका परीक्षा केंद्र रेलवे रोड स्थित वर्धमान एकेडमी में है।पिता का असमय चले जाना कुशल के लिए जीवन भर का दर्द दे गया। अंतिम संस्कार के लिए पहले शनिवार सुबह नौ बजे का समय निर्धारित किया गया, लेकिन कुशल की सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक परीक्षा थी। इसी को देखते हुए परिवार व समाज के लोगों में विचार-विमर्श हुआ। निर्णय लिया गया कि दोपहर बाद अंतिम संस्कार होगा और इकलौता पुत्र कुशल ही अंतिम संस्कार करेगा। कुशल अपनी आंखों में अश्रु व असाधारण धैर्य के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचा और परीक्षा दी। दोपहर दो बजे वह अश्रुधारा लेकर घर पहुंचा, जिसके बाद पार्थिव शरीर को सूरजकुंड स्थित श्मशान घाट ले जाया गया। कुशल ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। समाज के लोगों ने कहा कि कुशल ने एक तरफ पढ़ाई की परीक्षा दी तो दूसरी तरफ पुत्र धर्म होने का दायित्व निभाया।

पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने के लिए बंदूक-तमंचा लेकर दौड़ाया, वीडियो वायरल; चार पर मुकदमा दर्ज

» पंचायत चुनाव लड़ने वाले युवक को तमंचा-बंदूक से धमकाया।
» प्रधान समेत चार पर चुनाव रोकने, जान से मारने की धमकी का आरोप।
» आरोपियों पर पहले भी राजस्व टीम पर पथराव का मामला।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। तमंचा और बंदूक लेकर युवक को दौड़ाते हुए एक वीडियो रविवार की दोपहर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। इसे भगवानपुर गांव का बताया जा रहा है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। इसमें पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने के लिए धमकाने का आरोप लगाया गया है। प्रधान समेत चार पर मुकदमा लिखकर पुलिस जांच कर रही है। भगवानपुर के इशहाक पुत्र हसन अली ने कोतवाली देहात में तहरीर देकर बताया कि प्रधान पद का चुनाव लड़ने के लिए वह तैयारी कर रहे हैं। इसकी जानकारी पाकर गांव के विपक्षी नाराज हैं। रविवार को वह नमाज पढ़कर जा रहे थे।

क्या है आरोप? आरोप है कि इसी बीच गांव के प्रधान नादिर, वहीद, सुहेब, सद्दाम आदि ने उनको रास्ते में तमंचा व बंदूक लेकर दौड़ा लिया और मारपीट की। साथ ही चुनाव लड़ने पर जान से मारने और गांव में न रहने देने की धमकी दी। कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह ने बताया कि फायर नहीं हुआ है, वीडियो प्रकाश में आया है। तहरीर के आधार पर प्रधान नादिर, वहीद, सुहेब, सद्दाम पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

अधिकारियों पर पथराव कर चुके आरोपित

तत्कालीन नायब तहसीलदार सदर डा. अतुल सेन सिंह राजस्व टीम के साथ भगवानपुर में 27 सितंबर 2024 को भूमि पैमाइश करने गए थे। वहां टीम पर प्रधान समेत इन्हीं आरोपितों ने पथराव कर दिया था। सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके बाद डीएम के निर्देश पर आरोपितों पर मुकदमा लिखाया गया था।

बुन्देलखंड यूनिवर्सिटी के आवासीय परिसर में डॉक्टर ने लगाई फांसी, शव देख बेहोश हुई पत्नी

झांसी। बुन्देलखण्ड यूनिवर्सिटी के आवासीय परिसर में डॉक्टर डॉ. नीरज कुरील ने फाँसी लगाकर जान दे दी। घर काम करने पहुँची मेड ने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया। पर दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर पड़ोस आ गये। इसके बाद उनकी पत्नी प्रोफेसर राधिका को सूचना दी गई। राधिका के आने पर भी काफी देर तक जब दरवाजा नहीं खुला, तो गेट पर लगी जाली तोड़ी गई। कुण्डी खोलकर अन्द पहुँची राधिका पति का शव देखकर बेहोश हो गई। मृतक डॉ. नीरज कुरील का परिवार थाना प्रेमनगर क्षेत्र स्थित खाती बाबा मन्दिर के पास रहता है। उनकी पत्नी राधिका चौधरी बुन्देलखंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर राधिका अपने पति नीरज और दो बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी परिसर में रहती थीं। सूचना पाकर नवाबाद पुलिस मौके पर पहुँची। पुलिस ने घटना को लेकर जांच शुरू कर दी है।

ओडिशा में 13 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप के आरोप में 5 शिक्षक गिरफ्तार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। ओडिशा के केंद्रापाड़ा जिले में एक निजी इंग्लिश मिडिय स्कूल में रेप का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने कक्षा 7 की एक छात्रा के साथ कथित रूप से एक साल से अधिक समय तक दुष्कर्म करने के आरोप में 5 शिक्षकों को गिरफ्तार किया है. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक मामला तब सामने आया, जब नाबालिग पीड़िता ने पिछले महीने अपनी मां को पूरी घटना बताई. इसके बाद परिवार ने 18 फरवरी को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) में शिकायत दर्ज कराई. इसकी जानकारी बाल कल्याण समिति की सदस्य स्वागतिका पात्रा ने दी।

शिकायत मिलने के अगले दिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने स्कूल का दौरा कर मामले की जांच शुरू की और इसे संवेदनशील करार दिया. इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो (पाक्सो) एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

केंद्रापाड़ा के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ कटारिया ने बताया कि पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है और एफआईआर में नामजद पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्हें रविवार को अदालत में पेश किया जाएगा. एसपी ने कहा, 'यह एक संवेदनशील मामला है. मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों की टीम, जो महिला अपराध प्रकोष्ठ का हिस्सा है, जांच की निगरानी करेगी.' पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है।

परिवार का आरोप है कि छात्रा के साथ लंबे समय तक बार-बार दुष्कर्म किया गया। यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ अन्य शिक्षक, जिनमें एक महिला शिक्षक भी शामिल है, आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आरोपियों ने कथित तौर पर छात्रा को धमकी भी दी थी कि वह इस बारे में किसी को न बताए।

पीड़िता के परिवार का कहना है कि उन्होंने स्कूल प्रशासन को भी इस बारे में जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी परिवार की तरफ से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में शिकायत दर्ज कराने के बाद ही मिली। वहीं मामले पर प्रिंसिपल ने कहा, 'पूरी सच्चाई विस्तृत जांच के बाद ही सामने आएगी।'

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। प्रयागराज में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मामले में एडीजे रेप एवं पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने झूंसी थाना पुलिस को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है।

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

शाकुंभरी पीठाधीश्वर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट से जुड़े आशुतोष ब्रह्मचारी ने 28 जनवरी को धारा 173(4) के तहत अर्जी दाखिल कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी. उनका आरोप है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण होता है. उन्होंने इस संबंध में एक सीडी अदालत को सौंपने का भी दावा किया है।

मामले में 13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों के बयान अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए थे. कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया और सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है।

33 हजार वोल्ट की लाइन पर कूदा बंदर, 10 घंटे गुल रही 80 गांवों की लाइट

●बंदर के कूदने से 33 हजार वोल्ट लाइन प्रभावित।

सीतापुर के 80 गांवों में 10 घंटे बिजली गुल।

नैमिषारण्य उपकेंद्र की आपूर्ति हुई बाधित।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

औरंगाबाद (सीतापुर)। नैमिषारण्य उपकेंद्र जाने वाली 33 हजार वोल्ट लाइन पर चितवा पुल के पास रविवार की सुबह चार बजे बंदर कूद गया। इसके चलते 10 घंटे तक 80 गांवों की आपूर्ति ठप हो गई। फाल्ट को दुरुस्त करने में तीस मिनट तक नैमिषारण्य से ब्रेकडाउन लिया गया, जिसके बाद फाल्ट दुरुस्त हो सकी।

मिश्रिख के 132 केवी पारेषण खंड के उपकेंद्र से 33 हजार वोल्ट की लाइन नैमिषारण्य उपकेंद्र को जाती है। रविवार सुबह करीब चार बजे एक बंदर बिजली लाइन पर कूद गया। इसके चलते लाइन का इंसुलेटर टूटकर जमीन पर गिर गया और बंदर की भी मौत हो गई।

80 गांवों की बिजली गुल

इससे नैमिषारण्य ग्रामीण उपकेंद्र ठप गया और औरंगाबाद, रामपुर, रामशाला, बकेनिया फीडर से जुड़े बीबीपुर, भैरमपुर, परसपुर, मीरापुर, करुवामऊ, असरफनगर, लोधौरा, मानपुर सहित करीब 80 गांवों की बिजली गुल हो गई।

औरंगाबाद के फाजिल बेग, दानिश, फैजी ने बताया कि सुबह बिजली गुल होने से सहरी करने दिक्कत आई। सुबह-सुबह कटौती से दिनचर्या भी गड़बड़ा गई। जानकारी मिलने के बाद अवर अभियंता सौरभ अवस्थी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बंदर का अंतिम संस्कार करने के बाद फाल्ट को दुरुस्त करने में जुट गए। दोपहर दो बजे के करीब इन गांवों को बिजली मिल सकी। 33 हजार वोल्ट लाइन पर बंदर कूदने से नैमिषारण्य ग्रामीण उपकेंद्र बंद हो गया था। फाल्ट को दुरुस्त करने में काफी समय जरूर लग गया। इससे करीब 30 मिनट तक नैमिषारण्य कस्बे की भी बिजली गुल रही। - अंकुर वर्मा, उपखंड अधिकारी-मिश्रिख

अनुरक्षण कार्य के चलते 11 घंटे गुल रही बिजली

नगर की रविवार को 11 घंटे बिजली बाधित रही। उपखंड अधिकारी नगर रवि प्रकाश गौतम ने इस कटौती के बारे में पहले ही जानकारी दी थी। उन्होने बताया था कि सुबह आठ से शाम सात बजे तक पड़ाव पर रखे 630 केवीए का ट्रांसफार्मर बंद रहेगा। जिससे चलते मुख्य बाजार सहित तामसेन गंज मुहल्ले की बिजली बाधित रही। दिनभर कटौती से व्यापारियों को जरूर समस्या हुई।

मुफ्त की योजनाओं की लक्ष्मण रेखा तय करे सुप्रीम कोर्ट

देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा हाल ही में चुनावों से पूर्व राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता प्राप्ति के लिए मतदाताओं को आकर्षित करने हेतु घोषित लोकलुभावन मुफ्त योजनाओं की कड़ी आलोचना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रश्न उठाया है कि आखिर यह 'मुफ्त की योजना' वाली संस्कृति कब तक चलती रहेगी ? न्यायालय की यह चिंता राष्ट्रहित में अत्यंत उचित है, क्योंकि आज देश के अधिकांश राज्यों में मुफ्त योजनाओं के सहारे सरकार बनाने की परंपरा सी बन चुकी है । वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य ऐसा बन गया है कि कोई भी दल बिना मुफ्त की रेवड़ियां बाँटे केवल अपने विकास कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पाता। परिणामस्वरूप, सरकारें जनहित के विकास कार्यों पर व्यय होने वाले धन को मुफ्त योजनाओं के वादों को पूरा करने में खर्च कर देती हैं। इससे विकास कार्य या तो धनाभाव में रुक जाते हैं अथवा समय पर पूर्ण नहीं हो पाते। मुफ्त योजनाओं के बढ़ते बोझ के कारण राज्य सरकारों को बार-बार करोड़ों रुपये का कर्ज लेना पड़ता है। अनेक राज्य पहले से ही राजस्व घाटे में चल रहे हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मुफ्त योजनाओं पर खर्च किया जाने वाला धन अंततः करदाताओं की गाढ़ी कमाई का ही होता है। राजनीतिक दलों की लोकलुभावन घोषणाओं का बोझ अंततः आम नागरिकों पर ही पड़ता है । सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि मुफ्त योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों को मिलना चाहिए, न कि सक्षम और संपन्न वर्ग को। दुर्भाग्यवश, अनेक योजनाओं का बड़ा हिस्सा उन लोगों तक पहुँच जाता है जिन्हें उसकी वास्तविक आवश्यकता नहीं है, जबकि सचमुच जरूरतमंद आज भी सहायता के अभाव में संघर्ष करते दिखाई देते हैं।

मुफ्त योजनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति का एक सामाजिक दुष्प्रभाव भी सामने आ रहा है। जब बिना श्रम के लाभ मिलने लगता है, तो परिश्रम की भावना कमजोर पड़ने का खतरा उत्पन्न होता है। भारत सदैव से मेहनतकश और श्रमजीवी लोगों का देश रहा है। हमारे पूर्वजों ने अपने परिश्रम और स्वावलंबन की परंपरा से विश्व को प्रेरित किया है। ऐसे में मुफ्त की संस्कृति का अत्यधिक विस्तार चिंतन का विषय है । राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे मुफ्त योजनाओं के स्थान पर ऐसी दीर्घकालिक और सुनियोजित नीतियाँ बनाएँ, जो स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करें और लोगों को आत्मनिर्भर बनाएँ। यदि नागरिक अपने श्रम के बल पर जीवन स्तर सुधारेंगे, तो राष्ट्र की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ, जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली शामिल थे, ने इस विषय पर गंभीर चिंता व्यक्त की । न्यायालय का यह दृष्टिकोण सराहनीय है कि कल्याणकारी योजनाएं और चुनावी प्रलोभन इन दोनों के बीच स्पष्ट अंतर रेखांकित किया जाना चाहिए। यह भी चिंताजनक है कि मुफ्त की योजनाओं के कारण समाज में श्रम के प्रति अरुचि का भाव पनपने लगा है। यदि सरकारें बिना श्रम के संसाधन उपलब्ध कराती रहेंगी, तो आत्मनिर्भरता की भावना कमजोर पड़ेगी । भारत के मेहनतकश और श्रमजीवी लोगों ने अपने परिश्रम और उद्यमिता से विश्व में पहचान बनाई है। ऐसे में परिश्रम के स्थान पर निर्भरता की संस्कृति को बढ़ावा देना दूरगामी दृष्टि से घातक सिद्ध हो सकता है।आज स्थिति यह हो गई है कि सरकारें स्वयं की गई घोषणाओं के बोझ तले दबती जा रही हैं। यदि कोई सरकार मुफ्त योजनाओं में कटौती करने का प्रयास करती है, तो विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर और अधिक मुफ्त योजनाओं की घोषणा कर सत्ता परिवर्तन का प्रयास करता है। सत्ता खोने के भय से कोई भी दल इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का साहस नहीं जुटा पाता । ऐसे में देश की सर्वोच्च संस्था के रूप में सर्वोच्च न्यायालय से अपेक्षा है कि वह मुफ्त योजनाओं की एक स्पष्ट 'लक्ष्मण रेखा' निर्धारित करे। यदि कोई राजनीतिक दल मतदाताओं को अव्यावहारिक और आर्थिक रूप से अस्थिर करने वाली मुफ्त योजनाओं का प्रलोभन देकर चुनाव जीतने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध कठोर दिशा-निर्देश और वैधानिक प्रावधान होने चाहिए। यदि भारत को आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाना है, तो मुफ्त योजनाओं और लोकलुभावन राजनीति के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का अर्थ अंधाधुंध मुफ्त वितरण नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण, लक्षित और टिकाऊ विकास होना चाहिए। अब समय आ गया है कि राष्ट्रहित में इस विषय पर ठोस और दूरदर्शी निर्णय लिए जाएँ और मुफ़्त कि योजनाओ पर लक्ष्मण रेखा खीच कर उसका पालन सभी राजनीतिक दलों से कढ़ाई से करवाया जाए !

अरविंद रावल

क्या संभावित अमेरिका-ईरान युद्ध वैश्विक युद्ध का आगाज होगा

अमेरिका की भीषण जंगी तैयारी।

अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध की आशंका केवल राजनीतिक बयानबाज़ी तक सीमित नहीं रही है बल्कि उसके पीछे गहरी सामरिक तैयारियाँ और दीर्घकालिक सैन्य रणनीतियाँ भी काम कर रहीं हैं। अब अमेरिका अपनी जंगली लाव- लश्कर के साथ ईरान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी में तैनात हो गया है। अब यदि कभी प्रत्यक्ष युद्ध की स्थिति बनती है, तो यह समझना आवश्यक होगा कि अमेरिका विशिष्ट प्रकार की सैन्य तैयारी और युद्ध क्षमता के साथ मैदान में उतर सकता है, और ऐसी तैयारी किसी क्षेत्रीय संघर्ष को व्यापक वैश्विक टकराव की दिशा में धकेल सकती है। अमेरिका विश्व की सबसे सशक्त सैन्य शक्तियों में शुमार माना जाता है, जिसकी वैश्विक उपस्थिति अनेक महाद्वीपों में फैले सैन्य अड्डों, नौसैनिक बेड़ों और वायुसेना ठिकानों के रूप में दिखाई देती है। खाड़ी क्षेत्र में उसकी स्थायी और अस्थायी सैन्य तैनाती पहले से मौजूद है, जिसमें विमानवाहक पोत समूह, मिसाइल विध्वंसक जहाज़, पनडुब्बियाँ और उन्नत लड़ाकू विमान शामिल होते हैं। अमेरिकी सामरिक सिद्धांत 'फोर्स प्रोजेक्शन' पर आधारित है, अर्थात वह अपनी सैन्य शक्ति को दूरस्थ क्षेत्रों में तेज़ी से तैनात करने की क्षमता रखता है। अमेरिका की युद्ध तैयारी का एक प्रमुख आयाम उसकी वायु श्रेष्ठता है। अत्याधुनिक स्टील्थ लड़ाकू विमान, लंबी दूरी के बमवर्षक और ड्रोन नेटवर्क उसे शुरुआती चरण में शत्रु के वायु रक्षा तंत्र, संचार नेटवर्क और सामरिक ठिकानों को निष्क्रिय करने की क्षमता प्रदान करते हैं। किसी संभावित युद्ध में अमेरिका पहले चरण में 'शॉक एंड ऑ' जैसी रणनीति अपनाते हुए मिसाइल हमलों और सटीक बमबारी के माध्यम से ईरान की कमांड एंड कंट्रोल संरचना को कमज़ोर करने की कोशिश कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसकी साइबर युद्ध बड़ी ताकत है, जिसके माध्यम से वह शत्रु के विद्युत ग्रिड, बैंकिंग तंत्र और सैन्य संचार प्रणाली को बाधित कर सकता है।नौ-सैनिक दृष्टि से फारस की खाड़ी और होर्मुज़ जलडमरूमध्य सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि युद्ध छिड़ता है तो अमेरिकी नौसेना समुद्री मार्गों की सुरक्षा और ईरान की नौसैनिक गतिविधियों को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान देगी। विमानवाहक पोत समूह किसी भी तटीय लक्ष्य पर दूर से ही आक्रमण करने में सक्षम होते हैं। साथ ही पनडुब्बियों से दागी जाने वाली क्रूज़ मिसाइलें ईरान के भीतर गहरे स्थित ठिकानों तक पहुंच सकती हैं। अमेरिका की मिसाइल रक्षा प्रणाली और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ समन्वय भी उसकी तैयारी का हिस्सा होता है। अमेरिका की सामरिक तैयारी केवल प्रत्यक्ष युद्ध तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह अपने सहयोगी देशों और सैन्य गठबंधनों के माध्यम से दबाव बनाने की नीति भी अपनाता है। खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी अड्डे, क्षेत्रीय साझेदारों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास, और उन्नत हथियार प्रणालियों की तैनाती एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन भी होते हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक प्रतिबंध और वित्तीय नाकेबंदी भी अमेरिकी रणनीति का हिस्सा होते हैं, जिनका उद्देश्य शत्रु देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर युद्ध क्षमता को सीमित करना होता है।

हालांकि, यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि ईरान पारंपरिक युद्ध में अमेरिका से कमजोर होते हुए भी असममित युद्ध रणनीति में दक्ष माना जाता है। वह मिसाइलों, ड्रोन, समुद्री माइंस और प्रॉक्सी समूहों के माध्यम से अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों को निशाना बना सकता है। इसलिए अमेरिकी तैयारी में केवल आक्रमण ही नहीं, बल्कि रक्षा और क्षति-नियंत्रण की योजना भी शामिल रहती है। मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति मार्गों की रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। यदि इस संघर्ष में अन्य महाशक्तियाँ अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होती हैं, तो स्थिति और जटिल हो सकती है। रूस और चीन जैसे देश कूटनीतिक या सीमित सामरिक समर्थन के माध्यम से शक्ति संतुलन बनाने का प्रयास कर सकते हैं। वहीं इज़राइल अपनी सुरक्षा चिंताओं के कारण सक्रिय भूमिका निभा सकता है। ऐसी स्थिति में युद्ध क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर प्रभाव डाल सकता है, विशेषकर ऊर्जा बाज़ार और वैश्विक व्यापार पर। नअमेरिका की सामरिक तैयारी का एक महत्वपूर्ण पहलू उसकी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता भी है, यद्यपि परमाणु हथियारों का उपयोग अंतिम विकल्प माना जाता है। परमाणु त्रिस्तरीय प्रणाली भूमि आधारित मिसाइलें, पनडुब्बी से प्रक्षेपित मिसाइलें और रणनीतिक बमवर्षक उसे व्यापक प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती हैं। यही कारण है कि पूर्ण विश्व युद्ध की संभावना अपेक्षाकृत कम मानी जाती है, क्योंकि परमाणु शक्ति संतुलन बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष टकराव को रोकने में भूमिका निभाता है। अमेरिका की युद्ध तैयारी बहुआयामी, तकनीकी रूप से उन्नत और वैश्विक नेटवर्क पर आधारित है। यदि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होता है तो प्रारंभिक चरण में अमेरिका अपनी वायु, नौसैनिक और साइबर क्षमता का व्यापक उपयोग कर सामरिक बढ़त लेने का प्रयास करेगा। किंतु यह संघर्ष विश्व युद्ध में तब्दील होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अन्य महाशक्तियाँ किस हद तक प्रत्यक्ष रूप से शामिल होती हैं और कूटनीतिक प्रयास कितने सफल रहते हैं। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में प्रत्यक्ष विश्व युद्ध सभी के लिए विनाशकारी होगा, इसलिए संभावना अधिक यही है कि सामरिक तैयारी के बावजूद बड़े देश पूर्ण युद्ध से बचने का प्रयास करेंगे और संघर्ष को सीमित दायरे में रखने की रणनीति अपनाएँगे। वैश्विक स्तर पर यह लगातार प्रयास किया जा रहे हैं कि अमेरिका ईरान युद्ध जो बाद में वैश्विक युद्ध में परिवर्तित हो सकता है,को न होने दिया जाए अन्यथा प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध की तरह अमेरिका तीसरे विश्व युद्ध का निर्णायक देश फिर साबित होगा जो पूरे वैश्विक देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है।

संजीव ठाकुर

अमेरिकी करों का बदलता स्वरूप और भारत की रणनीति

ट्रंप प्रशासन द्वारा वैश्विक आयात पर लगाए गए नए करों ने अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक जगत में एक अभूतपूर्व हलचल पैदा कर दी है। वर्ष 2026 के शुरुआती महीनों में अमेरिकी शासन और न्यायपालिका के बीच जो खींचतान देखने को मिली हैए उसने भारत जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के लिए अनिश्चितता और अवसर दोनों की स्थिति उत्पन्न की है। 20 फ़रवरी 2026 को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में लगाए गए कुछ विशेष शुल्कों को अवैध ठहराते हुए यह स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों का असीमित उपयोग नहीं किया जा सकता। इस न्यायिक निर्णय ने भारत के लिए कुछ समय के लिए राहत की स्थिति उत्पन्न की थी क्योंकि इससे पारस्परिक करों की दर जो अठारह से पच्चीस प्रतिशत तक जा सकती थीए वह घटकर न्यूनतम व्यापारिक दरों पर आने की संभावना बन गई थी। किंतु इसके तुरंत बाद अमेरिकी नेतृत्व ने व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर पहले दस प्रतिशत और फ़िर पंद्रह प्रतिशत के नए शुल्कों की घोषणा कर दी। यह नए शुल्क 150 दिनों की अवधि के लिए लागू किए गए हैंए जिसका मुख्य आधार भुगतान संतुलन की समस्या को बताया गया है।

भारत के दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिका उसका सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य हैए जहाँ वह प्रतिवर्ष लगभग अठारह प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ अठहत्तर अरब डॉलर से अधिक का माल भेजता है। अमेरिकी प्रशासन का यह तर्क कि अन्य देश दशकों से उनका शोषण कर रहे हैं और व्यापार घाटे को कम करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैए भारत के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने इन परिस्थितियों का सूक्ष्मता से आकलन करना आरंभ कर दिया है। 25 फ़रवरी 2026 से प्रभावी होने वाले इन पंद्रह प्रतिशत के शुल्कों का सीधा प्रहार भारत के औषधीय निर्माणए वस्त्र उद्योग और अभियांत्रिकी वस्तुओं पर पड़ेगा। भारतीय औषधीय क्षेत्र का लगभग बीस प्रतिशत निर्यात केवल अमेरिका को होता हैए जो अब महंगा हो जाएगा। इसी प्रकार वस्त्र उद्योग में दस प्रतिशत की हिस्सेदारी और अभियांत्रिकी वस्तुओं की व्यापक पहुंच पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिकी वित्त विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि यद्यपि यह कदम वर्तमान में अस्थायी हैंए परंतु आने वाले समय में राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित अन्य धाराओं के अंतर्गत इन्हें स्थायी रूप से भी लागू किया जा सकता है।

भारत की प्रतिक्रिया इस पूरे विवाद में बहुत ही संतुलित और परिपक्व रही है। भारत सरकार ने नियम.आधारित व्यापार व्यवस्था पर जोर देते हुए यह स्पष्ट किया है कि वह बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की पक्षधर है। 7 फ़रवरी 2026 को जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा बदलाव करते हुए रूस से कच्चा तेल खरीदने की मात्रा कम करने और उसके बदले अमेरिका से ऊर्जाए सूचना प्रौद्योगिकी और कोयले की खरीद बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत आने वाले समय में अमेरिका से लगभग पांच सौ अरब डॉलर की खरीद कर सकता हैए जो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संतुलन को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। भारत का मानना है कि यदि द्विपक्षीय व्यापार समझौता सफ़लतापूर्वक संपन्न होता हैए तो वह इन अतिरिक्त शुल्कों से मुक्ति पा सकता है। भारतीय संघ बजट 2026 में भी इस दिशा में दूरदर्शिता दिखाई गई हैए जहाँ निर्यातकों को राहत देने के लिए सीमा शुल्क में कटौती की गई है। व्यक्तिगत आयात पर करों को बीस प्रतिशत से घटाकर दस प्रतिशत करना इसी रणनीति का हिस्सा है ताकि घरेलू विनिर्माण को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सके। भारत की आगामी रणनीति बहुआयामी होनी चाहिए ताकि अमेरिकी बाजार पर उसकी निर्भरता कम हो और वह एक स्वावलंबी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर सके। सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ निर्यात का विविधीकरण है। भारत को अब केवल अमेरिका पर केंद्रित न रहकर यूरोपीय संघए दक्षिण.पूर्वी एशियाई देशों के संगठन और अफ्रीकी महाद्वीप के उभरते बाजारों की ओर देखना होगा। उन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर पुनः विचार करना आवश्यक है जहाँ भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष घरेलू विनिर्माण क्षमता को सुदृढ़ करना है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से भारत ने पहले ही स्मार्टफ़ोन और विद्युत चालित वाहनों के क्षेत्र में सफ़लता प्राप्त की हैए जिसे अब अन्य क्षेत्रों में भी दोहराने की आवश्यकता है। मूल्य संवर्धन की श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ना भारत के लिए अनिवार्य है ताकि वह केवल कच्चे माल का निर्यातक न रहकर उच्च तकनीक वाली वस्तुओं का निर्माता बने। इस व्यापारिक विवाद ने शिमत्र.तटीयकरणश् की अवधारणा को भी जन्म दिया हैए जिसका अर्थ है कि अमेरिकी कंपनियां चीन जैसे देशों से अपना उत्पादन हटाकर भारत जैसे मित्र राष्ट्रों में स्थानांतरित करें। यह लंबी अवधि में भारत के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। यदि अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करती हैं और यहाँ से वैश्विक आपूर्ति सुनिश्चित करती हैंए तो टैरिफके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्तए भारत को विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी अपनी आवाज बुलंद रखनी होगी। यदि अमेरिकी प्रशासन धारा 122 का दुरुपयोग करता हैए तो भारत को अन्य प्रभावित राष्ट्रों के साथ मिलकर एक सामूहिक मोर्चा बनाना चाहिए। जी.20 और क्वाड जैसे समूह भी इस दिशा में कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। जवाबी कर लगाना एक अंतिम विकल्प होना चाहिएए क्योंकि इससे व्यापार युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होगीए जैसा कि हमने 2018 में देखा था।

डिजिटल सेवाओं और सॉफ्टवेयर निर्यात के क्षेत्र में भारत की स्थिति अधिक सुरक्षित है क्योंकि ये क्षेत्र भौतिक वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्कों से कम प्रभावित होते हैं। भारत को अपनी इस शक्ति का लाभ उठाना चाहिए। साथ हीए निर्यातकों के लिए बीमा योजनाओं और धन वापसी की प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा ताकि उनकी कार्यशील पूंजी अवरुद्ध न हो। अमेरिकी न्यायालय के निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि वहां की लोकतांत्रिक संस्थाएं राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश लगा सकती हैंए और भारत को अपनी कानूनी दलीलों और कूटनीतिक वार्ताओं में इस पक्ष का लाभ उठाना चाहिए। 150 दिनों की समय सीमा भारत के लिए एक अवसर की खिड़की है जिसमें वह अपनी मोलभाव करने की शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताएं इस गतिरोध को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

अंततःए ट्रंप प्रशासन की आक्रामक व्यापारिक नीतियां भारत को अपनी आर्थिक नीतियों के पुनर्मूल्यांकन का संदेश दे रही हैं। यह विवाद न केवल एक चुनौती हैए बल्कि भारत के लिए अपनी विनिर्माण शक्ति को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने का एक संकेत भी है। यदि भारत चतुराई और दृढ़ता के साथ अपनी रणनीति पर चलता हैए तो वह इस संकट को एक ऐसे अवसर में बदल सकता है जहाँ उसकी अर्थव्यवस्था और अधिक लचीलीए विविध और स्वतंत्र होकर उभरेगी। वैश्विक व्यापार के इस संक्रमण काल में भारत की भूमिका एक तटस्थ और नियम.पालक राष्ट्र की होनी चाहिए जो अपने हितों की रक्षा के साथ.साथ वैश्विक आर्थिक स्थिरता का भी सम्मान करे। संतुलित मार्ग ही वह एकमात्र रास्ता है जो भारत को एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जाएगा और उसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक विश्वसनीय केंद्र बनाएगा।

महेन्द्र तिवारी

संपादकीय

जगमगाते महानगरों के भीतर पनपती खामोश महामारी

[सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते लोग, भीतर से दरकते रिश्ते]

[महानगर: अवसरों की भूमि या संवेदनाओं का सूखा मैदान?]

पहले शहरों को उम्मीदों की फैक्ट्री कहा जाता था। यहाँ रोशनी कभी बुझती नहीं, सपने थकते नहीं और भीड़ ठहरती नहीं। फिर भी इस अनवरत चहल-पहल के बीच एक गहरी खामोशी जन्म ले रही है। 1.4 अरब लोगों के देश में, जहाँ हर प्लेटफॉर्म, हर चौराहा, हर बाज़ार भीड़ से अटा है, वहीं दिलों के भीतर सूनापन फैलता जा रहा है। ऊँची इमारतों की जगमगाती खिड़कियाँ बताती हैं कि लोग मौजूद हैं, पर मौजूदगी और अपनापन अलग बातें हैं। शहरों ने हमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा किया, मगर दिलों के बीच फासले बढ़ा दिए। यही फासला अब महामारी की तरह फैल रहा है। सर्वे बताते हैं कि 61 प्रतिशत भारतीय अकेलापन महसूस करते हैं, और युवाओं में यह दर सबसे अधिक है।

अकेलापन अब केवल निजी कमजोरी नहीं, हमारी सामाजिक बनावट की दरार है। महानगरों की दौड़ ऐसी है कि रिश्ते रास्ते में छूट जाते हैं। सुबह की सिटी बस या मेट्रो में सैकड़ों चेहरे साथ चलते हैं, पर कोई नज़र किसी पर ठहरती नहीं। सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स जुड़ते हैं, पर कठिन समय में सहारा देने वाला हाथ नहीं मिलता। डिजिटल जुड़ाव ने संवाद का आभास रचा, मगर उसकी संवेदना छीन ली। इमोजी हँसते हैं, पर असली मुस्कान की गर्माहट गायब है। यह बनावटी निकटता भीतर के शून्य को और गहरा करती है–मानो भीड़ के बीच खड़ा व्यक्ति अपने ही अस्तित्व से दूर हो गया हो। आज का शहर प्रतिस्पर्धा की प्रयोगशाला बन गया है, जहाँ हर व्यक्ति खुद को साबित करने की दौड़ में सांस ले रहा है। नौकरी की अस्थिरता, बढ़ती महँगाई, किराए का बोझ और करियर की अनिश्चितता मन पर अदृश्य दबाव बनाते हैं। आर्थिक सुरक्षा की खोज में लोग भावनात्मक सहारे से समझौता कर बैठते हैं। रिश्ते समय चाहते हैं, और समय सबसे महँगी पूँजी हो चुका है। परिवार सिमटते गए, पड़ोसी अपरिचित होते गए, दोस्तियाँ औपचारिकताओं में बदलती गईं। नतीजा यह कि इंसान सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता रहा, पर भीतर की सीढ़ियाँ दरकती रहीं। उपलब्धियों के शोर में दिल की धीमी आवाज़ कहीं खोती चली गई।

भारत जैसे देश में, जहाँ सामूहिकता परंपरा की पहचान रही है, वहाँ भी यह बदलाव साफ दिखता है। कभी आँगन में दादी की कहानियाँ गूँजती थीं, मोहल्ले की चौपालें सजती थीं और त्योहार मिलन का बहाना बनते थे। अब त्योहार इंस्टाग्राम स्टोरी बन गए हैं, परिवार व्हाट्सऐप ग्रुप तक सिमट गया है। संयुक्त परिवारों की जगह एकल जीवनशैली ने ले ली है। स्वतंत्रता तो बढ़ी है, पर सहारा कम हो गया है। आधुनिकता ने विकल्पों की भरमार दी, मगर उसी ने स्थायित्व छीन लिया। बदलते सामाजिक ढाँचे में व्यक्ति स्वायत्त तो हुआ, पर भीतर से और अधिक अकेला। यही विरोधाभास शहरों की गहरी त्रासदी बन चुका है। रोज़गार और बेहतर भविष्य की तलाश में लाखों लोग अपने कस्बों और गाँवों से दूर आ बसे हैं। इस बदलाव ने अवसर तो दिए, पर पहचान की मिट्टी छीन ली। नए शहर में सब कुछ नया होता है–भाषा की लय, व्यवहार की शैली, जीवन की रफ्तार। व्यक्ति रोज़ाना अनुकूलन करता है, पर भीतर कहीं जड़ों की तलाश बनी रहती है। त्योहारों पर घर न पहुँच पाने की कसक, अपनों की आवाज़ से दूरी और साझा स्मृतियों का अभाव मन को अनकहा बोझ दे जाता है। नए संबंध बनते हैं, पर पुराने जैसा सहज भरोसा नहीं पनपता। यह विस्थापन बाहर से उपलब्धि लगता है, भीतर से रिक्तता का कारण बन जाता है।

मानसिक स्वास्थ्य के आँकड़े इस सच को और तीखा कर देते हैं। अवसाद, चिंता और अनिद्रा की समस्याएँ तेज़ी से फैल रही हैं। विडंबना यह कि भीड़ से भरे शहरों में भी लोग अपनी पीड़ा चुपचाप ढोते हैं; मदद माँगना अब भी कमजोरी माना जाता है। सफलता की चमक के पीछे संघर्ष की छाया दिखती नहीं। कॉर्पोरेट दफ्तरों की जगमग इमारतों में बैठे अनेक लोग भीतर से दरके होते हैं। वे पेशेवर मुस्कान ओढ़े रहते हैं, पर निजी जीवन में संवाद का अभाव झेलते हैं। समाज ने उपलब्धियों को सराहा, पर भावनात्मक संतुलन को अनदेखा किया। यही असंतुलन अब धीमे-धीमे महामारी का रूप ले चुका है।

शहरों की बनावट भी इस अकेलेपन को गहरा करती है। गेटेड सोसायटी सुरक्षा तो देती हैं, पर ऊँची दीवारें संवाद के रास्ते बंद कर देती हैं। पड़ोसी वर्षों तक एक-दूसरे का नाम तक नहीं जानते। पार्कों में लोग साथ-साथ चलते हैं, पर अपनी-अपनी दुनिया में गुम रहते हैं। सार्वजनिक स्थल सिमट रहे हैं, और निजी स्क्रीन फैलती जा रही हैं। बच्चे मैदानों से ज्यादा मोबाइल पर समय बिताते हैं। बुजुर्ग अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे झाँकते हैं, पर बातचीत का अवसर दुर्लभ है। भौतिक विकास ने सुविधाएँ बढ़ाई, पर मानवीय स्पर्श घटा दिया। यही स्पर्शहीनता दिलों को भीतर से बंजर बना रही है।

फिर भी इस अँधेरे में आशा की लौ टिमटिमा रही है। कई शहरों में सामुदायिक पहलें जन्म ले रही हैं, जहाँ लोग पुस्तक क्लबों, कला कार्यशालाओं और सामाजिक समूहों के जरिये फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर संवाद शुरू हुआ है। नई पीढ़ी अपनी भावनाएँ व्यक्त करने में पहले से अधिक निर्भीक दिखती है। कार्यस्थलों पर वेलनेस कार्यक्रम और लचीले समय की अवधारणा भी जगह बना रही है। यह संकेत है कि समाज समस्या को पहचानने लगा है। और पहचान ही समाधान की पहली सीढ़ी होती है। जब हम स्वीकारते हैं कि अकेलापन सच है, तभी उससे लड़ने की दिशा में ठोस कदम उठते हैं। अंततः प्रश्न यह नहीं कि शहरों में कितने लोग बसते हैं, बल्कि यह कि कितने दिल सचमुच जुड़े हैं। 1.4 अरब की आबादी में भी यदि व्यक्ति खुद को अनसुना पाए, तो कमी संख्या में नहीं, संवेदना में है। हमें संवाद की संस्कृति को फिर से सांस देनी होगी। रिश्तों में वही निवेश करना होगा, जो हम करियर में करते हैं। पड़ोसी से परिचय, मित्र से बेझिझक बात, परिवार के साथ बिताया समय–ये छोटे कदम बड़े बदलाव की नींव बन सकते हैं। शहर तब सचमुच जीवंत होंगे, जब उनमें रहने वाले लोग एक-दूसरे की धड़कन सुन सकेंगे। भीड़ के बीच भी अपनापन संभव है–बस हमें ठहरकर किसी का हाथ थामने का साहस जुटाना होगा।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

बंगाल में 'दीदी बनाम मोदी' की सीधी जंग, तमिलनाडु में द्रविड़ किले पर 'विजय' फैक्टर की दस्तक

देश की सियासत एक बार फिर दो बड़े गैर-भाजपा शासित राज्यों,पश्चिम बंगाल और तमिलनाडुकी ओर टिकी है। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो चुकी है और राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है। एक ओर बंगाल में 'दीदी बनाम मोदी' की सीधी लड़ाई आकार ले रही है, तो दूसरी ओर तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति के पारंपरिक द्वंद्व के बीच अभिनेता विजय की एंट्री ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इन दोनों राज्यों के चुनाव न केवल क्षेत्रीय राजनीति की दिशा तय करेंगे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों पर भी गहरा असर डाल सकते हैं। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डेढ़ दशक से सत्ता में हैं। 34 साल तक चले वाम शासन के 'लाल किले' को भेदकर सत्ता में आई ममता आज भी आक्रामक तेवर में नजर आती हैं। उनके लिए महिला मतदाता, अल्पसंख्यक समर्थन, सामाजिक योजनाएं और मजबूत बूथ कैडर चुनावी आधार की धुरी हैं। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने ग्रामीण और महिला वोट बैंक में गहरी पैठ बनाई है। इसके साथ ही ममता की सड़क पर उतरकर संघर्ष करने वाली छवि पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरती है। हाल के महीनों में भर्ती घोटाले, मंत्रियों की गिरफ्तारी, हजारों नियुक्तियों के रद्द होने और कुछ चर्चित घटनाओं ने सरकार की छवि पर सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन ममता इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए सीधे मुकाबले की रणनीति अपना रही हैं।

दूसरी ओर, भाजपा ने बंगाल में पिछले चुनाव में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की थी। 2021 के चुनाव में पार्टी ने 77 सीटें जीतकर खुद को मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित किया। भाजपा की रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे, 'डबल इंजन' सरकार के वादे और संगठित बूथ प्रबंधन पर टिकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय नेताओं के दौरे लगातार बढ़ रहे हैं। पार्टी घुसपैठ, भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध और कानून-व्यवस्था को मुख्य मुद्दा बना रही है। फिर भी भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य स्तर पर ममता के कद का सर्वमान्य चेहरा खड़ा करना है। स्थानीय नेतृत्व की कमी और बंगाली अस्मिता के सवाल पर टीएमसी की आक्रामक राजनीति भाजपा के लिए कठिन परीक्षा बन सकती है।

बंगाल की राजनीति में 'सड़क की ताकत' को निर्णायक माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जो सड़क पर दिखता है, वही चुनावी धारणा गढ़ता है। फिलहाल ममता की सक्रियता और संगठन की जमीनी मौजूदगी उन्हें बढ़त देती दिखती है, लेकिन भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ा है और पार्टी अपने समर्थकों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश में है कि सत्ता परिवर्तन संभव है। वाम दल और कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि विपक्षी वोटों का बिखराव होता है तो इसका सीधा लाभ टीएमसी को मिल सकता है।

तमिलनाडु की तस्वीर अलग है, लेकिन उतनी ही रोचक। यहां पांच दशकों से द्रविड़ दलों का वर्चस्व कायम है। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और विपक्षी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के बीच रहा है। 2021 में डीएमके ने बहुमत हासिल कर सत्ता में वापसी की थी। मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन सामाजिक कल्याण योजनाओं, क्षेत्रीय अस्मिता और केंद्र के साथ टकराव की राजनीति को आधार बना रहे हैं। हिंदी थोपने के आरोप और संघीय ढांचे के मुद्दे को भी डीएमके जोर-शोर से उठा रही है।

एआईएडीएमके, जो कभी जे. जयललिता के नेतृत्व में मजबूत धुरी थी, उनके निधन के बाद से आंतरिक खींचतान से जूझ रही है। पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। भाजपा राज्य में अपनी स्वतंत्र पहचान मजबूत करना चाहती है और 50 से अधिक सीटों की मांग कर रही है, जबकि एआईएडीएमके सीमित साझेदारी के पक्ष में है। भाजपा की कोशिश एआईएडीएमके से अलग हुए नेताओं को फिर से साथ लाकर व्यापक एनडीए खड़ा करने की है।

तमिलनाडु की राजनीति में इस बार सबसे बड़ा नया फैक्टर अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) है। युवाओं और दक्षिण तमिलनाडु में विजय की लोकप्रियता ने चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की संभावना बढ़ा दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि टीवीके 10-15 प्रतिशत वोट भी हासिल करती है तो यह पारंपरिक समीकरणों को बदल सकता है। विजय खुद को भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। उन्होंने डीएमके और भाजपा दोनों से दूरी बनाकर तीसरे मोर्चे की संभावना खुली रखी है।

कांग्रेस इस राज्य में डीएमके के साथ गठबंधन में है और अधिक सीटों की मांग कर रही है, लेकिन अंतिम फैसला सीट शेयरिंग वार्ता पर निर्भर करेगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए तमिलनाडु में विस्तार की चुनौती बरकरार है, क्योंकि यहां राष्ट्रीय दलों की भूमिका अब तक सीमित रही है।

दोनों राज्यों में एक समान तत्व है।पहचान की राजनीति और कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव। बंगाल में जहां महिला और अल्पसंख्यक वोट निर्णायक माने जाते हैं, वहीं तमिलनाडु में सामाजिक न्याय, भाषा और क्षेत्रीय गर्व का मुद्दा अहम है। भाजपा इन दोनों राज्यों में अपनी जड़ें गहरी करने की कोशिश में है, लेकिन उसे स्थानीय भावनाओं और मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्व की दीवार से जूझना पड़ रहा है।

आगामी चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन या पुनरावृत्ति का प्रश्न नहीं हैं। यह क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय राजनीति की परीक्षा भी है। बंगाल में यदि ममता फिर जीतती हैं तो उनका कद राष्ट्रीय विपक्ष की धुरी के रूप में और मजबूत होगा। वहीं भाजपा यदि सीटों में बड़ी बढ़त दर्ज करती है तो पूर्वी भारत में उसका विस्तार नया अध्याय लिखेगा। तमिलनाडु में डीएमके की वापसी द्रविड़ मॉडल की पुष्टि मानी जाएगी, जबकि एआईएडीएमके-भाजपा गठबंधन की सफलता दक्षिण भारत में भाजपा की संभावनाओं को नई ऊर्जा दे सकती है। और यदि विजय की पार्टी उल्लेखनीय प्रदर्शन करती है, तो यह राज्य की राजनीति में स्थायी बदलाव की शुरुआत हो सकती है। इस तरह 2026 के विधानसभा चुनाव बंगाल और तमिलनाडु में केवल सरकार चुनने का अवसर नहीं, बल्कि राजनीतिक दिशा तय करने की निर्णायक घड़ी बनते जा रहे हैं। देश की निगाहें अब इन दो राज्यों पर टिकी हैं, जहां हर रैली, हर बयान और हर गठबंधन भविष्य की राजनीति की पटकथा लिख रहा है।फिर भी कयास लगाए जा रहे है कि मतदाता जंगलराज से परेशान है ओर इसकी तैयारी कर चुकी भाजपा जीत का दावा कर परिवर्तन की पूर्ण सम्भावना बताई जा रही है।

कांतिलाल मांडोत

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः**-उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। **R.N.I NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0 -9511151254,** E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

संक्षिप्त खबरें

मलिहाबाद के ग्राम पंचायत बिराहिमपुर में आवास सूची में गड़बड़ी का आरोप, जांच की मांग

मलिहाबाद (लखनऊ)। राजधानी लखनऊ के विकासखंड मलिहाबाद की ग्राम पंचायत बिराहिमपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सचिव पर अपात्र लोगों के नाम आवास सूची में शामिल करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर गांव में नाराज़गी का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि जिन लोगों के नाम आवास सूची में डाले गए हैं, उनके पहले से ही पक्के मकान बने हुए हैं। आरोप है कि पात्रता दिखाने के लिए नहर किनारे बनी झोपड़ी को आधार बनाकर उनके नाम सूची में शामिल कर दिए गए, जबकि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल सका। इस संबंध में ग्रामीणों ने तहसील दिवस में प्रभारी अधिकारी को लिखित शिकायत पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि यदि मामले की गहराई से जांच कराई जाए तो आवास सूची में की गई कथित अनियमितताओं का खुलासा हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पात्रता की दोबारा जांच कर वास्तविक लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाए और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब देखना यह है कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं।

विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत भराये गये फार्म

ए0ई0आर0ओ0 ने किया बूथों का निरीक्षण।

बिसवां (सीतापुर)। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी के निर्देश पर शनिवार 22 फरवरी को विधानसभा 150 सेवता अन्तर्गत बिसवां तहसील के मतदान केन्द्र उच्च प्राथमिक विद्यालय कम्पोजिट जहांगीराबाद पर विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत बूथ लगाकर नये मतदाताओं के लिए फार्म-6 तथा परिवर्धन के लिए फार्म- 8 तथा अपमार्जन के लिए फार्म- 7 भरवाने का कार्य किया गया। इस दौरान बूथ संख्या 265 से 272 का निरीक्षण ए0ई0आर0ओ0 डा0 आशाराम वर्मा ने किया। उनके साथ सुपरवाइजर के रूप में क्षेत्रीय लेखपाल नीलेश कुमार यादव भी मौजूद थे। रविवार दोपहर 2 बजे तक बूथ संख्या 265 से 271 तक 71 मतदाताओं ने फार्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवाया वहीं 25 लोगों ने फार्म-8 भरकर संशोधन करवाया वहीं 3 फार्म-7 भरकर अपमार्जन करवाया। निरीक्षण में ए0ई0आर0ओ0 ने सभी बीएलओ से फार्म 6 व 8 की उपलब्धता तथा उन्हें भरवाये जाने के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा नोटिसों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर बीएलओ सुनीता वर्मा, अफरोज जहां, मेहनाज बेगम, फिरोज आलम, शीला श्रीवास्तवा, निशा वर्मा, सुमन कुमारी वर्मा, सुनीता देवी वर्मा एवं प्रधान प्रतिनिधि मुशीर अहमद, बीएलए सुधाकर मिश्र, कन्हैया रस्तोगी व वकार अहमद आदि मौजूद रहे।

पुलिस की सख्त कार्रवाई: 16 गिरफ्तार, 88 वाहनों का चालान

भदोही। जनपद भदोही पुलिस द्वारा कानून-व्यवस्था सुदृढ़ रखने हेतु चलाए गए अभियान के तहत 01 वारंटी सहित कुल 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय भेजा गया। थाना गोपीगंज पुलिस ने वारंटी कैलाशनाथ पुत्र विश्वनाथ निवासी पुरेबहरिया को गिरफ्तार किया। वहीं थाना भदोही, औराई, दुर्गागंज एवं चौरी पुलिस द्वारा शांति भंग की आशंका में धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चालान किया गया। इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए 70 दोपहिया व 18 चारपहिया सहित कुल 88 वाहनों का चालान किया गया।

विद्युत संविदा कर्मियों का हल्ला बोल: 25,000 वेतन और नियमितीकरण की मांग, छंटनी होने पर कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी

● .....लखनऊ में आयोजित कार्यकारिणी बैठक में विद्युत संविदा मजदूर संगठन ने राज्य सरकार के समक्ष रखीं अपनी प्रमुख मांगें।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के नरही स्थित केंद्रीय कार्यालय में रविवार को नवल किशोर सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक में संविदा कर्मियों के हितों को लेकर हुंकार भरी गई, जिसमें संरक्षक आर.एस. राय और प्रदेश प्रभारी पुनीत राय समेत कई प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार से मांग की गई कि ऊर्जा निगमों के संविदा कर्मियों को आउटसोर्स कर्मचारी निगम में शामिल किया जाए, जोखिमपूर्ण कार्य के बदले अकुशल श्रमिकों को ?22,000 व लाइनमैन/एसएसओ/कंप्यूटर ऑपरेटर को ?25,000 मासिक वेतन दिया जाए, और 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मियों को नियमित सेवा में समायोजित कर सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष निर्धारित की जाए। इसके साथ ही संगठन ने मार्च 2023 की हड़ताल के दौरान हटाए गए कर्मियों की पुनर्बहाली, फेशियल अटेंडेंस व्यवस्था की समाप्ति, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर ?20 लाख करने पर जोर दिया, साथ ही यह चेतावनी भी दी कि यदि प्रदेश के किसी भी जिले में कर्मियों की छंटनी की गई, तो संगठन वहां लोकतांत्रिक तरीके से पूर्ण कार्य बहिष्कार पर विचार करेगा। इस दौरान बैठक में संगठन के संरक्षक व वरिष्ठ मजदूर नेता आर.एस. राय, अरुण कुमार, राजेश्वर सिंह, सुनील सिंह, अशोक पाल, संजय सिंह, धनंजय राजभर, श्याम नारायण यादव, आनंद सिंह, विपिन विश्वकर्मा, सोहन मौर्य, प्रियांशु सिंह समेत भारी संख्या में पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे।

निर्धारित समय से पहले मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में लटका ताला, मरीज लौटे निराश

मुख्यमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य मेला बना मजाक......

लालगंज (रायबरेली)। ऐहार के नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य मेला अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ता नजर आया। मेले का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित था, लेकिन लगभग तीन बजे दोपहर में ही अस्पताल के मुख्य गेट पर ताला लटका मिला। इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचे कई मरीजों को मायूस होकर लौटना पड़ा। कुछ महिलाएं अपने छोटे बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंची थीं, लेकिन गेट बंद देख सभी हैरान रह गए। दूर-दराज गांवों से आए लोगों ने बताया कि अस्पताल परिसर में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। काफी देर इंतजार और पूछताछ के बावजूद स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी। मरीजों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य मेले का आयोजन करती है, लेकिन यदि निर्धारित समय से पहले ही अस्पताल बंद हो जाए तो योजना का लाभ कैसे मिलेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से शासन की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं।

1805 मतदेय स्थलों पर चला विशेष पुनरीक्षण अभियान, डीएम ने किया निरीक्षण

तुलसीपुर (बलरामपुर)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में जनपद के चारों विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत रविवार को सभी 1805 मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा मतदाताओं से दावे एवं आपत्तियां प्राप्त कर मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया संचालित की गई। जनपद के सभी बूथों पर बीएलओ निर्धारित समय पर उपस्थित रहे और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, विवरण संशोधन तथा अन्य आवश्यक कार्यों को संपादित किया। प्रत्येक बीएलओ के पास फॉर्म-06 सहित सभी निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध रहे, जिससे मतदाताओं को आवेदन करने में सुविधा मिली। मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिए सहायता डेस्क भी स्थापित किए गए, जहां आमजन को आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार जैन ने तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड हरैया सतघरवा अंतर्गत बूथ संख्या-90 (उच्च प्राथमिक विद्यालय शिवपुरा) तथा बूथ संख्या 177 से 180 (उच्च प्राथमिक विद्यालय मंगरोहोल) का स्थलीय निरीक्षण कर अभियान की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने फॉर्म-06 के संकलन एवं प्राप्त दावों-आपत्तियों की स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा सभी कार्य पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए। विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी ईआरओ/एईआरओ द्वारा भी निरंतर मतदेय स्थलों का भ्रमण कर अभियान की मॉनिटरिंग की गई और मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे अपने मतदाता विवरण की जांच अवश्य करें तथा नाम जोड़ने, संशोधन या अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी निभाएं, ताकि निर्वाचन नामावली को शुद्ध, पारदर्शी एवं अद्यतन बनाया जा सके।

उद्यान मंत्री ने तीन दिवसीय सरस मेला का किया शुभारंभ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रायबरेली:- राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात उ0प्र0 दिनेश प्रताप सिंह ने आज जीआईसी के मैदान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तत्वाधान में आयोजित 'जनपद स्तरीय तीन दिवसीय सरस मेला-2026 ' का फीता काटकार उद्घाटन कर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा स्वःनिर्मित उत्पादों की विक्रय एवं प्रदर्शनी के लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। इसके पश्चात दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी,मुख्य विकास अधिकारी अंजू लता, जिला विकास अधिकारी अरुण कुमार, उपायुक्त श्रम रोजगार प्रमोद सिंह, उपायुक्त एन0 आर0 एल0 एम0 सविता सिंह उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में उद्यान मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 04 महिला समूह की महिलाओं को 07 करोड़ 63 लाख से अधिक का डमी चेक देकर सम्मानित किया। योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले खंड विकास अधिकारी दीनशाहगौरा अशोक कुमार सचान, खंड विकास अधिकारी अमावां संदीप कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी लालगंज गगनदीप सिंह एवं बैंक स्तर पर उत्कर्ष कार्य करने वाले अग्रणी बैंक प्रबंध रुपेश दुबे, क्षेत्रीय प्रबंधक अनुज कुमार यादव व शैलेंद्र प्रताप सिंह को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में आदर्श स्वयं सहायता समूह की महिला गंगा सिंह ने बताया कि उन्होंने लगभग 258 समूह का गठन कर महिलाओं को समूह से जोड़कर खुद भी सशक्त व आत्मनिर्भर बनने के साथ अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया।

इस अवसर पर मंत्री जी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व व मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मातृ शक्ति को स्वावलंबी व सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है, आज देश व प्रदेश में महिलाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर उनको सशक्त बनाकर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज आप छोटे-छोटे कार्यों से लेकर महिलाओं के समूह के कार्यों का आकलन करेंगे तो आपको गर्व होगा कि हमारी मातृ शक्ति सशक्त, स्वावलंबी बनकर आगे बढ़ रही है हर क्षेत्र में देश, प्रदेश व जनपद का नाम रोशन कर रही है।

धन्यवाद ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम में उपनिदेशक कृषि विनोद कुमार, उपायुक्त उद्योग परमहंस मौर्य, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मोहन त्रिपाठी, जिला समाज कल्याण अधिकारी सृष्टि अवस्थी, जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह, जिला उद्यान अधिकारी जयराम वर्मा सहित संबंधित अधिकारी व समूह की महिलाएं, लाभार्थीगण आदि उपस्थित रहे।

अनाया फतिमा ने रखा रमजान का पहला रोजा

लहरपुर सीतापुर नगर के मोहल्ला चौपड़ी टोला की रहने वाली 10 वर्ष की बच्ची अनाया फतिमा ने रखा रमजान का पहला रोजा जहां बच्चों की परवरिश में माता-पिता की बहुत ही अहम भूमिका होती है। माता-पिता की आदतों को देखकर ही बच्चों को बड़ी नसीहत मिलती है। अनाया फातिमा के पिता मो0 एहसान बेग व माता उम्मे कुलसुम ने बेटी के रोजा रखने में भरपूर सहयोग दिया। रमजान का माह चल रहा है यह माह बड़ी बरकतों वाला है मुस्लिम समाज में रमजान के माह में बड़े बुजुर्ग महिलाएं पुरुषो को रोजा रखने का बड़ा उत्साह होता है। वही नन्हे मुन्ने बच्चे भी रोजा रखने में कही बड़ो से पीछे नही है। पाक महीना इस्लाम धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी माह में इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी किताब कुरान पैगंबर मोहम्मद साहब को अवतरित हुई थी। मुस्लिम समाज इस रमजान के पूरे माह मे रोजा (उपवास) रखकर प्रार्थना करके व दान देकर अल्लाह के प्रति भक्ति संयम और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं यह आत्म अनुशासन सहानुभूति और आध्यात्मिक शुद्धि का समय है।

रहीमाबाद थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक संपन्न: होली और ईद पर आपसी भाईचारे और शांति की अपील

● ......शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, इंस्पेक्टर अरुण कुमार त्रिगुणायक ने संभ्रांत नागरिकों के साथ की समन्वय बैठक।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मलिहाबाद, लखनऊ। आगामी प्रमुख त्योहारों होली और ईद-उल-फितर के शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रविवार को लखनऊ के रहीमाबाद थाना परिसर में एक महत्वपूर्ण 'पीस कमेटी' (शांति समिति) की बैठक आयोजित की गई। रहीमाबाद थाना प्रभारी (इंस्पेक्टर) अरुण कुमार त्रिगुणायक की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में क्षेत्र के विभिन्न समुदायों के धर्मगुरुओं, ग्राम प्रधानों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य एजेंडा त्योहारों के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना और सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करना रहा।

बैठक को संबोधित करते हुए इंस्पेक्टर अरुण कुमार त्रिगुणायक ने कहा कि भारत की संस्कृति साझा विरासत की है, जहाँ होली और ईद जैसे त्योहार आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे के संदेश देते हैं। उन्होंने सभी से अपील की कि वे इन पर्वों को अपनी परंपराओं के अनुसार हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन इस दौरान दूसरों की भावनाओं का भी पूरा सम्मान करें। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है; किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर, अफवाह या आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि किसी ने भी क्षेत्र की शांति व्यवस्था को भंग करने या कानून हाथ में लेने की कोशिश की, तो उसके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

क्षेत्र की सुरक्षा रणनीति पर चर्चा करते हुए पुलिस प्रशासन ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों को चिह्नित कर लिया गया है, जहाँ अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा, क्षेत्र में नियमित गश्त (पैट्रोलिंग) बढ़ाई जाएगी ताकि आमजन खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। बैठक में मौजूद हिंदू-मुस्लिम दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों ने पुलिस का समर्थन करते हुए आश्वासन दिया कि मलिहाबाद और रहीमाबाद का क्षेत्र हमेशा से अपनी गंगा-जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता रहा है और इस बार भी सभी नागरिक मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाएंगे।

पुराने साथियों से मिलकर हुई मौज मस्ती

● चंद्रभानु में एल्युमिनाई मीट में ताजा हुईं यादें।

महाविद्यालय की हर तरह मदद करें छात्र: डॉ टीपी सिंह

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। चन्द्र भानु गुप्त कृषि महाविद्यालय में एल्युमिनाई मीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 32 वर्ष पुराने दोस्त गेट- टूगेदर के माध्यम से मिले और महाविद्यालय के दिनों की यादों को ताजा किया। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉ फिदा हुसैन अंसारी एवं प्रबंधक डॉ टीपी सिंह ने सरस्वती जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर प्रारंभ किया। महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र के सदस्यों को पौधा देखकर स्वागत किया गया तथा पूर्व छात्र- छात्राओं ने अपने अनुभव एवं विचार साझा किए,पुरातन सम्मेलन में रंगारंग कार्यक्रमों का आनंद लिया और साथ में भोजन किया। मुख्य अतिथि डॉ फिदा हुसैन अंसारी ने पुराने दोस्तों से मिलने की खुशी को अवर्णनीय बताया और बताया कि श्रद्धेय भगवती सिंह जी द्वारा स्थापित किया गया महाविद्यालय पूरे भारत में जाना जाता है इसे अच्छा करने में सभी सहयोग करें । महाविद्यालय के प्रबंधक डॉ टी पी सिंह ने कहा कि महाविद्यालय के पुरातन छात्र के महाविद्यालय के गौरव को ऊंचा करने में मदद करे महाविद्यालय के विकास में समर्पण भाव से योगदान करें। रविवार को महाविद्यालय में ये अद्भुत नजारा देखने को मिला।जहां एल्युमनाई मीट में गेट-टू-गेदर होकर सेलिब्रेशन किया गया। महाविद्यालय पुराने दोस्तों ने खूब ठहाके लगाए तथा एक-दूसरे को गले लगाया। महाविद्यालय के पुरातन छात्र आर सी गुप्ता ने बताया की इस महाविद्यालय का मैं छात्र रहा आज हमने अपनी कंपनी बनाई है मेरी कंपनी में बायोटेक्नोलॉजी,बायो पेस्टीसाइड, स्मार्ट बायो उर्वरक के उत्पाद बनाये जाते हैं और किसानों को कम दरों में उपलब्ध करायें जाते हैं। जिसमें हम महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को रोजगार दे रहे हैं।

आस्ट्रेलिया में शिक्षक पद पर कार्यरत महाविद्यालय के पुरातन छात्र डॉ तुलसीराम भुसाल ने कहा की महाविद्यालय का शिक्षण कार्य बहुत बेहतर है इसका लाभ लेना चाहिए। महाविद्यालय के मिडिया प्रभारी डॉ सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस महाविद्यालय का मैं पुरातन छात्र हूं आज इसी विधालय में शिक्षक हूं विधालय में 32 वर्ष से छात्र और शिक्षक के रूप में जुड़ा हूं। लगभग 7500 कृषि स्नातक एवं 900 परास्नातक कृषि छात्र- छात्राएं इस महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं जो पुरे भारत तथा विदेशों में सेवाएं दे रहे हैं। महाविद्यालय के हजारों छात्र-छात्राएं शिक्षक राजनीति वैज्ञानिक और उद्यमी के रूप आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र के सदस्य अशोक सिंह व डॉ बैजनाथ रावत,जितेंद्र निगम प्रशासनिक अधिकारी शिवमंगल चौरसिया, समन्वयक अधिकारी अजय भदोरिया, डॉ हृदय नारायण तिवारी, डॉ सुधीर कुमार रघुवंशी डॉ सुधाकर सिंह, पुरातन छात्र डॉ आशुतोष श्रीवास्तव सहित सभी शिक्षक कर्मचारी एवं महाविद्यालय के 150 से अधिक पुरातन छात्रो ने प्रतिभाग किया।

रास्ते का विवाद बना खूनी संघर्ष, दो पक्षों में जमकर मार-पीट, सात घायल

● अस्पताल में फिर भड़का गुस्सा, सिपाही की सूझबूझ से टली बड़ी वारदात।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे के पूरे देवी रामलीला मैदान मोहल्ले में रविवार को रास्ते के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्ष आमने सामने आ गए और उनके बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षो से सात लोग घायल हो गए। इनमे दो की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया। मोहल्ले में रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। मामला कई बार तहसील और पुलिस तक पहुंचा लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। रविवार को विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। एक पक्ष से अजमेर, मंजू सोनी और कमला गंभीर रूप से घायल हुए। दूसरे पक्ष से सौरभ, प्रदीप और संतोष को चोटें आई। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां अजमेर और प्रदीप की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल भेज दिया।

अस्पताल में ईट-पत्थर लेकर दौड़ाया

प्रदीप इलाज के बाद बाहर एंबुलेंस का इंतजार कर रहा था। तभी अजमेर की हालत बिगड़ गई। उसे उल्टियां होने लगीं। इस पर परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने प्रदीप और संतोष को ईट-पत्थर लेकर दौड़ा लिया। अस्पताल में मौजूद सिपाही साजन ने तुरंत हस्तक्षेप किया। दोनों युवकों को भागने को कहा। उनके हाथों से ईट पत्थर छीनकर दूर फेंका। दोनों युवक जान बचाकर करीब 500 मीटर दूर चमनगंज मोहल्ले में एक घर में घुस गए। भीड़ वहां भी पहुंच गई। पीछे पीछे सिपाही साजन भी दौड़ते हुए पहुंचे। घरवालों से निवेदन कर दोनों को अंदर सुरक्षित कराया। इस दौरान मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई।

आधे घंटे तक नहीं पहुंची एंबुलेंस

अजमेर को रेफर करने के बाद करीब आधे घंटे तक एंबुलेंस नहीं आई। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने तत्परता दिखाई। अपने वाहन से घायल को जिला अस्पताल भिजवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोहल्ले में तनाव को देखते हुए पुलिस तैनात की गई है।

श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली की एनएसएस इकाई का सात दिवसीय विशेष शिविर प्रारंभ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिधौली, सीतापुर। दिनांक 22 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की इकाई, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली द्वारा नगर पंचायत सिधौली के मोहल्ला लोधपुरवा स्थित पंचायत भवन में सात दिवसीय विशेष शिविर का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह आयोजन विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना, कर्तव्यपरायणता एवं राष्ट्रनिर्माण के प्रति प्रतिबद्धता विकसित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि साहित्यकार डॉ. देवेंद्र कश्यप 'निडर' तथा डॉ. गोपाल सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। अपने उद्बोधन में अतिथियों ने राष्ट्रीय सेवा योजना के मूल उद्देश्यों– 'नॉट मी, बट यू' की भावना–को रेखांकित करते हुए स्वयंसेवकों को निःस्वार्थ सेवा, अनुशासन, नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक समरसता के पथ पर अग्रसर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल शैक्षणिक उपलब्धि नहीं, बल्कि संवेदनशील एवं उत्तरदायी नागरिक का निर्माण है। प्रथम दिवस पर 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' विषयक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से स्वयंसेवकों ने बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता एवं सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन का संदेश जन-जन तक पहुँचाया। ग्रामीण अंचल में सकारात्मक संवाद स्थापित कर विद्यार्थियों ने समाज में जागरूकता का वातावरण निर्मित किया, जो इस शिविर की सार्थकता को परिलक्षित करता है।

विशिष्ट अतिथि डॉ. चंद्रशेखर प्रजापति ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे विशेष शिविर युवाओं के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा व्यवहारिक ज्ञान को समृद्ध करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को सेवा-भाव को जीवन का अभिन्न अंग बनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अजय वर्मा ने समस्त अतिथियों, स्वयंसेवकों एवं क्षेत्रवासियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि आगामी दिनों में स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता, सामाजिक सर्वेक्षण तथा जनकल्याणकारी गतिविधियों का क्रमबद्ध संचालन किया जाएगा।

श्री श्याम सत्संग भवन पुरैनी गंज में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया श्री श्याम सतरंगी फाल्गुनी अमृत महोत्सव

● सुप्रसिद्ध भजन गायिका उपासना मिश्रा ने सुन्दर भजनों का बांधा समां।

पूरे पंडाल में मौजूद श्याम भक्तों को किया सम्मोहित।

बाबा के भजनों में रात भर झूमे श्रद्धालु, खेली गयी फूलों की होली, हुआ गजरा उत्सव।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां (सीतापुर)। श्री श्याम सत्संग भवन पुरैनी गंज में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शनिवार को शाम 7 बजे से श्री श्याम सतरंगी फाल्गुनी अमृत महोत्सव 2026 बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूरी रात सभी श्रद्धालु भक्त खाटू श्याम के सुन्दर भजनों में डुबकी लगाते रहे। इसके अलावा हवन कुंड की अग्नि से अखंड श्याम ज्योति का आविर्भाव हुआ। श्री खाटू श्याम जी का फूलों द्वारा विशेष अलौकिक श्रंगार कर उन्हें छप्पन भोग लगाया गया। इस अवसर पर बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ फूलों की होली खेल कर गजरा उत्सव भी मनाया गया। भक्तों ने हवन पूजन किया तथा आशीर्वाद लिया।कार्यक्रम में सीतापुर से पधारी सुप्रसिद्ध भजन गायिका ने अपने भजनों से समां बांध दी। उनके भजनों को सुनकर पूरा पंडाल झूम उठा। उनके सुन्दर भजनों से श्रद्धालु इतना सम्मोहित हो गये कि भोर पहर तक उठने का नाम ही नहीं लिया। भजन गायक अम्बर श्रीवास्तव ने 'देवा ओ देवा गणपति देवा......' गणेश वंदना गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भजन गायक राहुल सिंधी ने गाया 'बाबा तुम जो मिल गये फूलों जैसे खिल गये' भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

बाराबंकी से पधारे गायक शानू सोनी ने 'मेरी नैय्या का खेवैय्या है मेरा सांवरा' भजन गाकर सबको नाचने पर मजबूर कर दिया।कार्यक्रम में भक्तों को श्याम खजाना भी दिया गया।

इस दौरान आयोजक सांवरा सेठ एवं संयोजक श्री श्याम परिवार के शिव प्रसाद सिंघल, बसंत खेतान, विजय कुमार अग्रवाल,अमित सिंघल,पंकज खेतान, मनीष बंसल,रवि प्रकाश बंसल,राज कुमार अग्रवाल,अमन श्रीवास्तव, नितिन मंगल, प्रदीप जायसवाल व विकास सहित पुरैनी गंज व आसपास क्षेत्र के सैकड़ों महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद रहे।आयोजकों द्वारा कलाकारों सहित गणमान्य लोगों का श्रीश्याम चुनर डालकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत व सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम भोर पहर तक चलता रहा।

संक्षिप्त खबरें

शोक समाचारः अपना दल (एस) नेता आकाश पटेल के पिता मुन्ना पटेल का निधन, क्षेत्र में शोक की लहर

शोक समाचारः अपना दल (एस) नेता आकाश पटेल के पिता मुन्ना पटेल का निधन, क्षेत्र में शोक की लहर

शोक समाचारः अपना दल (एस) नेता आकाश पटेल के पिता मुन्ना पटेल का निधन, क्षेत्र में शोक की लहर अपना दल (एस) के प्रदेश सचिव (श्रमिक मंच) एवं प्रमुख व्यापारी नेता आकाश पटेल को गहरा पितृ शोक पहुँचा है। उनके पिता श्री मुन्ना पटेल जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे पिछले 5 महीनों से अस्वस्थ चल रहे थे और जीवन के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे थे। मुन्ना पटेल जी का जीवन संघर्ष और सादगी की मिसाल था। उन्होंने शून्य से शुरुआत कर जमीन से जुड़कर अपने परिवार को खड़ा किया। उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनका 'संयुक्त परिवार' रहा, जिसे उन्होंने जीवन भर एक सूत्र में पिरोकर रखा। वे अपने पीछे चार पुत्र, एक पुत्री और नाती-पोतों से भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। मुन्ना पटेल जी केवल एक पारिवारिक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि समाज के प्रति भी अत्यंत संवेदनशील थे। उनके विचारों में हमेशा समाज के दबे-कुचले और कमजोर वर्ग के लिए विशेष स्थान रहता था। उनकी नजर में जो भी व्यक्ति असहाय दिखता, वे उसकी मदद के लिए तत्पर रहते थे। उनके निधन से न केवल परिवार बल्कि क्षेत्र के उन तमाम लोगों में शोक है जिन्होंने उनका स्नेह पाया था। उनके निधन की सूचना मिलते ही व्यापारिक जगत और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। विभिन्न दलों के नेताओं और व्यापारियों ने आकाश पटेल और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

'मेरे बयान को काटकर पेश किया गया', JNU कुलगुरु ने दलित टिप्पणी विवाद पर दी सफाई

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की कुलगुरु शांतिश्री डी पंडित ने दलितों और अश्वेतों संबंधी अपनी हालिया टिप्पणी पर उठे विवाद के बीच स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि उनके बयान को राजनीतिक उद्देश्य से संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किया गया। कुलगुरु ने कहा कि बड़ी संख्या में शिक्षकों ने उनका समर्थन किया है और आरोप लगाया कि जेएनयू शिक्षक संघ व छात्रसंघ परिसर में विचार-विमर्श की स्वस्थ परंपरा को चयनात्मक प्रस्तुति से प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कोई भी समुदाय स्थायी रूप से पीड़ित मानसिकता रखकर प्रगति नहीं कर सकता, जिस पर छात्र संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई। कुलगुरु ने स्पष्ट किया कि उनका बयान किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि पहचान की राजनीति पर टिप्पणी था। उन्होंने कहा कि वे समानता के पक्ष में हैं और जन्म-आधारित पहचान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव या दंड का समर्थन नहीं करतीं। उन्होंने भीमराव आंबेडकर का हवाला देते हुए कहा कि वे भी असमान कानून के पक्ष में नहीं होते। कुलगुरु ने कहा कि पूरा पाडकास्ट लगभग 55 मिनट का है और विवादित हिस्सा अंत का छोटा अंश है, जिसे गलत तरीके से प्रसारित किया गया। उन्होंने बताया कि कुछ सामाजिक चिंतकों, जैसे विवेक कुमार ने भी उनके बयान को सही संदर्भ में समझा है।

ग्रेटर नोएडा में 12 लाख कीमत का 80 किलो गांजा बरामद, दो ड्रग तस्कर दबोचे गए

ग्रेटर नोएडा। मेरठ की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) टीम ने सूरजपुर कोतवाली पुलिस के साथ 80 किलो गांजा बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गांजा की कीमत करीब 12 लाख रुपए होने का अनुमान है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से क्रेटा कार जब्त की है, इसी से गांजा की सप्लाई करते थे। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार के मुताबिक, शनिवार रात पुलिस टीम रेलवे पुल के पास सर्विस रोड पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एएनटीएफ टीम पहुंची। टीम ने बताया कि बादलपुर कोतवाली के दुजाना गांव निवासी रविंद्र नागर और बुलंदशहर निवासी मोंटी क्रेटा कार से कासना होकर परी चौक होते हुए गांजा लेकर सूरजपुर की तरफ सप्लाई करने आ रहे हैं। पुलिस टीम ने कुछ देर बाद आई क्रेटा कार रोकने का इशारा किया तो चालक मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। दोनों टीमों ने वाहन को घेर कर रोक कर गांजा बरामद किया। पूछताछ में आरोपित चालक रविन्द्र नागर ने बताया कि वर्तमान में लोटस पार्क सोसायटी सूरजपुर में रहता है। मोंटी सूरजपुर कस्बा में रहता है। बताया कि पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से एक अज्ञात व्यक्ति से गांजा लेकर आते थे, जिसे झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों, ट्रक और आटो चालकों के बीच खपाते थे। पुलिस नेटवर्क से जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही है। दोनों के खिलाफ विभिन्न थानों में करीब 12-12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रभारी निरीक्षक ने बताया दोनों पर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

जिले में 85 स्वीकृत पदों की जगह 36 चिकित्सक दे रहे सेवाएं

● **मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलना बनी मृग मरीचिका**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिनेश चौधरी

शहडोल उमरिया स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध सरकार की करनी और कथनी का सही अंदाज लगाने के लिए जिला चिकित्सालय उमरिया में उपलब्ध चिकित्सकों का आंकड़ों ही पर्याप्त है, जहाँ पर जिले भर में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिले की जनसंख्या के अनुपात में 85 चिकित्सकों के पद स्वीकृत किये गए हैं परंतु इनके जगह पर कुल 36 चिकित्सक ही सेवाएं दे पा रहे हैं, अभी भी 59 चिकित्सकों की कमी बनी हुई है।बिषय विशेषज्ञों के अभाव में यह काम साधारण चिकित्सकों से कराया जाता है।चिकित्सकों की इस कमी को लेकर सतत् रूप से आवाज उठायी जाती रही है लेकिन नगाड खाने में तूती की आवाज सुनाई नहीं देती की कहावत को चरितार्थ हो रही है ? उमरिया जिले में चिकित्सकों की इस कमी का असर यहाँ के मरीजो को भुगतना पड़ता है, फिर भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी व्ही के चंदेल जी ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने के लिए रात दिन की मशक्कत करते हुए पटरी पर बना रखी है। जिले भर में मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए लगातार निगरानी करते हुए जिले भर की आवाज को सुनकर उनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का सराहनीय प्रयास करते हैं।मुख्य चिकित्सा अधिकारी का उद्देश्य यह है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये हमारा अमला सतत रूप से सक्रिय रहकर काम करता है फिर भी अगर कही कोई शिकायत आती है तो त्वरित निदान करा कर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराया जाता है । गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को बिषय विशेषज्ञों के अभाव में मेडिकल कालेज भेजकर इलाज कराया जाता है। वैसे भी चिकत्सको की कमी होने के कारण जिले भर के मरीजों का भार जिला चिकित्सालय पर बना रहता है। जिले में डॉक्टरों और विशेषज्ञों के कुल 85 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 36 डॉक्टर और विशेषज्ञ ही सेवाएं दे रहे हैं। यह स्थिति जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक बनी हुई है।

जिला व सामुदायिक अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी

जिला चिकित्सालय में भी डॉक्टरों की कमी गंभीर है। यहां डॉक्टर और विशेषज्ञों के 30 स्वीकृत पदों में से केवल 9 पदों पर ही डॉक्टर कार्यरत हैं, जबकि 21 पद खाली हैं। मेडिकल ऑफिसर के 19 स्वीकृत पदों में से सिर्फ एक ही पदस्थ है, जिससे 18 पद रिक्त हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति भी चिंताजनक है। विशेषज्ञों के 11 पद स्वीकृत होने के बावजूद एक भी विशेषज्ञ तैनात नहीं है। डॉक्टरों के कुल 7 पदों में से केवल 3 डॉक्टर कार्यरत हैं, जबकि 4 पद खाली पड़े हैं।

पीएचसी में 18 में से सिर्फ 4 डॉक्टर तैनात

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी डॉक्टरों की भारी कमी है। यहां मेडिकल डॉक्टरों के 18 पद स्वीकृत हैं, लेकिन सिर्फ 4 डॉक्टर ही सेवाएं दे रहे हैं, जिससे 14 पद रिक्त हैं। वर्तमान में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था 19 बांडेड डॉक्टरों के माध्यम से संचालित की जा रही है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व्ही.के. चंदेल ने बताया कि रिक्त पदों की जानकारी लगातार उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि कम संसाधनों और सीमित स्टाफ के बावजूद मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

साइबर ठगी और 'सिस्टम' के दंश से टूटी हिम्मत, युवक ने की सुसाइड की कोशिश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उरई (जालौन)- जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहाँ साइबर फ्रॉड के चंगुल में फंसे एक युवक ने न्याय न मिलने और दलालों के कथित दबाव से क्षुब्ध होकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। युवक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।

पूरी घटना जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार, कदौरा का रहने वाला पीड़ित फैजान अहमद साइबर अपराधियों के झांसे में आ गया था। अहसान नामक ठग ने उसे कमीशन का लालच दिया और हमीरपुर स्थित एक्सिस बैंक में एक जॉइंट खाता खुलवाया। बताया जा रहा है कि इस खाते के जरिए करीब 4 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया। मोटी रकम ट्रांसफर होने के बाद साइबर ठगों ने युवक को उसका हिस्सा देने के बजाय पूरी रकम का गबन कर लिया। ठगी का शिकार होने के बाद युवक ने न्याय की उम्मीद में पुलिस का दरवाजा खटखटाया था। उसने जालौन पुलिस में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और आईटी एक्ट की धारा 66 डी के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया था। आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद न्याय मिलने के बजाय युवक 'पुलिस के दलालों' के निशाने पर आ गया। पीड़ित के पिता कल्लू ने बताया कि कुछ बिचौलिए और दलाल मामले को रफा-दफा करने के नाम पर युवक पर लगातार पैसों का दबाव बना रहे थे। इस पूरी घटना में एक कथित ऑडियो क्लिप भी सामने आया है, जिसमें दलाल और पीड़ित युवक के बीच बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। इस ऑडियो में मामले को निपटाने के बदले रुपयों की मांग की जा रही है। इसी मानसिक दबाव और आर्थिक तंगी के चलते युवक ने घर पर फांसी लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की। वहीं परिजनों ने युवक को फंदे पर लटकता देख तत्काल नीचे उतारा और गंभीर हालत में राजकीय मेडिकल कॉलेज, उरई में भर्ती कराया। डॉक्टरों के अनुसार युवक की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

जेएनयू में विरोध प्रदर्शन और हड़तालों से छात्रों की पढ़ाई हो रही प्रभावित, ABVP ने उठाए गंभीर सवाल

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में चल रहे ताजा विवाद के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की जेएनयू इकाई ने प्रशासनिक कदमों और वामपंथी छात्र संगठनों की भूमिका पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। संगठन का आरोप है कि अनुशासनात्मक कार्रवाइयों में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया, जिससे सामान्य छात्रों की पढ़ाई और परिसर का शैक्षणिक माहौल प्रभावित हो रहा है। एबीवीपी के अनुसार, पहले उसके कार्यकर्ताओं पर जुर्माना और निष्कासन जैसी कार्रवाइयों के समय छात्रसंघ चुप रहा, जबकि अब कुछ वामपंथी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई होते ही विरोध प्रदर्शन और हड़तालें की जा रही हैं। संगठन ने इसे 'चयनात्मक विरोध' बताते हुए कहा कि इससे छात्रहित से अधिक राजनीतिक स्वार्थ झलकता है। जेएनयू इकाई के अध्यक्ष मयंक पंचाल ने कहा कि परिषद शुरू से ही छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पारदर्शिता की पक्षधर रही है तथा किसी भी छात्रविरोधी नियम का विरोध करती रहेगी। वहीं मंत्री प्रवीण कुमार पीयूष ने कहा कि परिषद सिद्धांत आधारित छात्र राजनीति में विश्वास रखती है और कक्षाएं बाधित करने या अराजक गतिविधियों का समर्थन नहीं करती। संगठन ने प्रशासन से सभी छात्रों के लिए समान और पारदर्शी नीति अपनाने की मांग की है, ताकि परिसर में शैक्षणिक वातावरण सामान्य रह सके।

गोविन्दनगर शुगर मिल कर्मचारियों के हक में आया फैसलाः देना होगा 14 करोड़ का भुगतान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बस्ती। बस्तीजिलेके गोविन्दनगर शुगर मिल वाल्टरगंज के कर्मचारियों का बकाया पिछले 7 वर्षो से नहीं मिल पा रहा है. मिल प्रबंधन द्वारा बकाया भुगतान न किये जाने पर कर्मचारियों ने उप श्रमायुक्त से बकाया भुगतान दिलाने का आग्रह किया. उप श्रमायुक्त रचना केसरवानी ने मिल प्रबंधतंत्र को आदेश दिया है कि 209 मिल कर्मचारियों को लगभग 14 करोड़ रूपये श्रमिक रिटेनिंग एनाउन्स का भुगतान 30 दिन के भीतर सुनिश्चित कराया जाय. इससे मिल कर्मियों में खुशी की लहर है। रविवार को गोविन्दनगर शुगर मिल परिसर में कर्मचारियों ने एक दूसरे को मिठाईयां खिलाकर खुशियों को साझा किया.सत्येन्द्र बहादुर सिंह व अन्य बनाम मैसेर्स गोविन्दनगर शुगर मिल वाल्टरगंज के मामले में अलग-अलग आदेशों में उप श्रमायुक्त ने लगभग 14 करोड़ रूपये का श्रमिक रिटेनिंग एनाउन्स दिये जाने का आदेश दिया है. यदि निर्धारित समय में बकाया राशि का भुगतान न किया गया तो जिलाधिकारी के माध्यम से वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

उप श्रमायुक्त के आदेश की जानकारी देते हुये गोविन्दनगर शुगर मिल वाल्टरगंज के कर्मचारी मुकेश कुमार श्रीवास्तव, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, सुनील कुमार राव, रामतौल चौधरी और राममणि ने बताया कि यदि आदेश का शीघ्र पालन न हुआ तो वे संघर्ष तेज करने पर बाध्य होंगे। उप श्रमायुक्त के आदेश से गोविन्दनगर शुगर मिल वाल्टरगंज के कर्मचारियों में खुशी की लहर है. विकास ठाकुर, अरुण गिरी, अनिल चौधरी, संजय सिंह, राकेश सिंह, ध्रुव चंद चौधरी, कृष्ण चंद्र लाल, लाल मोहन, पतरी सिंह, चित्रभान सिंह, आशीष सिंह, रविंदर, रमेश रामकेवल, हृदयराम, प्रकाश सिंह, वीरेंद्र चौधरी, जसवंत सिंह आदि ने एक दूसरे को मिठाईयां खिलाकर खुशियों को साझा किया।

बीसीडी चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन पर 67 अधिवक्ता निलंबित, रिटर्निंग ऑफिसर ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट परिसर के अंदर चल रहे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) के चुनाव के मतदान में रविवार को चुनाव आचार संहिता का जमकर उल्लंघन हुआ। आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर व दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) तलवंत सिंह ने एक सख्त आदेश दिया। चुनाव समिति ने कहा कि मतदान क्षेत्र के पास गंभीर उल्लंघनों की रिपोर्ट मिली है और इससे जुड़े सुबूत मिले हैं, जिसे सत्यापित किया गया है। आदेश में कहा गया कि प्रत्याशियों के समर्थकों ने वोटिंग-बूथ के पास नारे लगाए, प्रचार सामग्री बांटी, टेंट और फ्लेक्स होर्डिंग लगाने के साथ ही बिना इजाजत बाहरी लोगों को तैनात किया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि बिना इजाजत बाहरी लोगों को तैनात करने से मतदाताओं के साथ ही चुनाव के सही तरीके से होने में रुकावट आई। निलंबित होने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता केके मनन, पूर्व बीसीडी चेयरमैन केसी मित्तल, हिमल अख्तर, महमूद प्राचा सहित अन्य शामिल हैं। निलंबित उम्मीदवार इस आदेश के खिलाफ 12 घंटे के अंदर अपील दायर कर सकते हैं।

सोमवार को जारी रहेगा बीसीडी चुनाव के लिए मतदान

शनिवार के बाद रविवार को भी बीसीडी चुनाव के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। रविवार को भी बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे। शनिवार को 17 हजार से अधिक लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। बीसीडी के 23 सदस्यों के पद के लिए हो रहे चुनाव के लिए मतदान सोमवार को भी जारी रहेगा।

दिल्ली के कल्याणपुरी में महिला हेड कॉन्स्टेबल से मोबाइल ले उड़े बदमाश, ड्यूटी से लौट रही थीं घर

पूर्वी दिल्ली। कल्याणपुरी इलाके में बदमाशों का दुस्साहस जारी है। बाइक सवार बदमाश दिनदहाड़े दिल्ली पुलिस की एक हेड कॉन्स्टेबल से मोबाइल झपटकर ले गए। महिला पुलिसकर्मी के साथ हुई झपटमारी ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था जग जाहिर कर दी है। पीड़िता स्वाति सिंह की शिकायत पर कल्याणपुरी थाना ने झपटमारी का केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है बदमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

स्वाति सिंह अपने परिवार के साथ विनोद नगर में रहती हैं। वह दिल्ली पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल हैं और उनकी तैनाती मध्य जिले में हैं। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि वह शनिवार को ड्यूटी के बाद सिविल ड्रेस में ऑटो से विनोद नगर पहुंची। जैसे ही वह ऑटो से नीचे उतरी, तभी एक बाइक पर दासे बदमाश आए और झपट्टा मारकर मोबाइल ले उड़े।

सिलापथार में युवक की लाश बरामद, थाने में शिकायत दर्ज, परिवार का संदेह हत्याकांड

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

असम धेमाजी। सिलापथार एक नंबर सिलागांव की जानकी देव नाथ के 21साल उम्र का बेटा जयंत देब नाथ ने बीतेकल शाम को अपने गांव के दोस्त सुब्रत दास, प्रवीण बैद्य, रतन वैद्य के साथ घर से टहलने निकले थे। लेकिन जयंत रात 8 बजे तक घर ना आने पर परिवार के लोगों ने आस पास में खबर करने लगी बदकिस्मत से रात के करीब 10 बजे सिला जनजाति हाई स्कूल के पीछे सुनसान इलाके फिशरी के तट पर मृत अवस्था में बरामद किया। परिवार के लोगों ने तुरन्त सिलापथार पुलिस थाने में खबर दी पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को बरामद कर पुलिस स्टेशन ले गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है।

परिवार ने यह भी दावा किया कि जयंत को प्लानिंग करके हत्या की गई है। परिवार के लोगों ने उल्लेखित टहलने निकली तीनों दोस्तों की नाम में आरोप लगाकर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई। घटना की जांच कर अपराधियों को कड़ी सजा देने कि मांग की। दूसरी ओर इस घटना को तीव्र निंदा करते हुए सौदों असम नाथ योगी सात्र संस्था के आंचलिक समिति के सचिव अजीत नाथ और नाथ योगी सम्मेलन की सिलापथार आंचलिक समिति के सचिव नीरद नाथ ने प्रशासन से घटना की सही जांस कर अपराधियों को कड़ी सजा देने कि मांग की है।

बलिया बेल्थरा रोड में वन दरोगा पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का केस, उच्चाधिकारियों के निर्देश पर दर्ज हुआ मुकदमा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलिया बेल्थरा रोड में वन दरोगा पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का केस, उच्चाधिकारियों के निर्देश पर दर्ज हुआ मुकदमा बलिया बेल्थरा रोड क्षेत्र में तैनात एक वन दरोगा पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर उभांव थाना पुलिस ने आरोपी उग्रसेन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

पीड़िता ने 3 फरवरी को थाने में दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि वन दरोगा ने विवाह का वादा कर करीब आठ महीने तक उसका शारीरिक शोषण किया। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का यह भी कहना है कि प्रारंभिक शिकायत के बावजूद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की। अधिकारियों के निर्देश पर उभांव पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 और धारा 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उभांव एसएचओ संजय शुक्ला ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है। गिरफ्तारी को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, जबकि सूत्रों के अनुसार आरोपी पुलिस की हिरासत में बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है।

गंगा बहुउद्देशीय सभागार में वृहद विधिक सहायता शिविर, डीएम-जिला जज-एसपी ने किया निरीक्षण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलिया। जनपद बलिया में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के तत्वावधान में गंगा बहुउद्देशीय सभागार में 'वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर' का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के साथ पुलिस विभाग ने भी भागीदारी करते हुए कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए जागरूकता कैम्प लगाया। कार्यक्रम का निरीक्षण जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, जिला जज अनिल कुमार झा एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने संयुक्त रूप से किया। अधिकारियों ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया।

शिविर में बलिया पुलिस द्वारा मिशन शक्ति, साइबर सुरक्षा, डायल 112 सेवा और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं को साइबर अपराध से बचाव, हेल्पलाइन सेवाओं के उपयोग और आत्मसुरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि वे शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित विभागों से संपर्क करें।

अंग्रेजी का पेपर रहा स्कोरिंग, लंबे उत्तर को लिखना बनी चुनौती; आपस में चर्चा करते दिखे परीक्षार्थी

नोएडा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से 10 वीं कक्षा का शनिवार को अंग्रेजी विषय का पेपर आयोजित किया गया। प्रश्न पत्र हाथ में आते ही छात्रों ने राहत की सांस ली। परीक्षा केंद्र से निकलते ही छात्रों के बीच पेपर का स्तर का चर्चा का विषय बन गया। छात्रों का कहना था कि प्रश्न पत्र आसान था। पेपर पूरी तरह संतुलित और स्कोरिंग था। कम्यूनिकेशन सेक्शन आसान और लिटरेचर पूरी तरह एनसीईआरटी के आधार पर रहा। जिस तरह गणित के पेपर ने परेशान किया था उतना ही अंग्रेजी के विषय ने काफी राहत तो दी लेकिन लंबे प्रश्न लिखने के साथ समय पर पूरा करने की चेतावनी भी रही। अंग्रेजी विषय की शिक्षिका शीतल सिंह ने बताया कि प्रश्नपत्र काफी बेहतर, संतुलित और पाठ्यक्रम पर आधारित था। सेट 1 और 2 में थोड़े कठिन प्रश्न जरूर थे लेकिन सेट 3 का प्रश्नपत्र सरल था। रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर इन सभी सेक्शन में विद्यार्थी को परखने के दृष्टिकोण से उचित प्रश्न पूछे गए थे। वहीं, पिछले वर्षों के सेंपल पेपर्स के अभ्यास से विद्यार्थियों को प्रश्नपत्र हल करने में सहजता हुई। सीबीएसई 12 वी कक्षा का फैशन स्टडीज और आटोमोटिव विषय का पेपर आयोजित किया गया।

थारू समाज की संस्कृति, इतिहास और अधिकार जागरूकता पर संगोष्ठी आयोजित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलरामपुर। थारू समाज की सांस्कृतिक पहचान, ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण एवं सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नीलम चौधरी (प्रधान) द्वारा किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न पदाधिकारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने सहभागिता करते हुए समाज को संगठित होकर आगे बढ़ने का संदेश दिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. विजय बहादुर चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मूल आदिवासी जनजाति कल्याण संस्था भारत वर्ष, रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह आयोजन केवल एक पुस्तिका या पत्रिका के विमोचन तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने गौरवशाली इतिहास को स्मरण करने, विशिष्ट थारू संस्कृति का सम्मान करने और समाज को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का एक सशक्त प्रयास है। उन्होंने नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने और शिक्षा के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर राकेश चौधरी, अध्यक्ष, जनजागृति सेवा संस्थान, महाराजगंज, शुभम भरत चौधरी, पदाधिकारी, थारू जनजाति सेवा संस्थान, महाराजगंज, अशोक कुमार चौधरी, ऑडिटर, थारू जनजागृति सेवा संस्थान, महाराजगंज, प्रदीप चौधरी, उपाध्यक्ष, जनजागृति सेवा संस्थान, महाराजगंज, धनिराम चौधरी, संरक्षक, जनपद बलरामपुर, हीरालाल, महामंत्री, बलरामपुर,

सहित अन्य समाजसेवी एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि समाज की एकजुटता ही उसके विकास का आधार है। जब तक समुदाय अपने इतिहास, संस्कृति और अधिकारों को समझकर संगठित रूप से आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक समग्र विकास संभव नहीं है। कार्यक्रम में सामाजिक जागरूकता, सांस्कृतिक संरक्षण और सामुदायिक उत्थान के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया गया।